घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 284- शुक्रवार 14- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया....

संसद सत्र खत्म : लोकसभा 1 मिनट,राज्यसभा 1 घंटे चली,बंदर के खिलौने के साथ विपक्ष का प्रदर्शन

नई दिल्ली,13 अगस्त 2026। संसद का मानसून सत्र गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट चली,जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे चली। लोकसभा में पीएम मोदी,गृह मंत्री अमित शाह,पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। स्पीकर ओम बिड़ला ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। वहीं,राज्यसभा में आखिरी दिन एमएमडीआर संशोधन बिल पास हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया।

लोकसभा में 114 घंटे में से 96 घंटे काम नहीं हुआ

मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन की सामान्य बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहता है। यानी एक दिन में करीब 6 घंटे कार्यवाही का समय होता है। इस हिसाब से 19 बैठकों में करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी,लेकिन यह करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली। यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम कार्यवाही हुई। वहीं, 2025 का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चला था। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की 21-21 बैठकें हुईं। लोकसभा में सिर्फ 37 घंटे काम हुआ था।

नड्डा बोले...भाजपा हल्द्वानी शुद्धिकरण की घटना का समर्थन नहीं करती

राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा...'खड़गे जी ने जो कहा...वह बेहद दुःखद है। यह सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं,बल्कि हम सभी के लिए दुख की बात है। बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। कभी नहीं। लेकिन हम इसकी जांच करेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वहां जो कुछ हुआ,उसकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी।' मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। मैं इसकी निंदा करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले को देखेंगे। यह हम सभी के लिए बेहद अफसोस की बात है कि आपकी भावनाएं आहत हुईं। सभापति राधाकृष्णन ने कहा...छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यह पाप है। हम सभी शुद्ध हैं। मामले की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए।

मानसून सत्र में 12 नए बिल पेश, 11 दोनों सदनों में पास : 2026 के मानसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए। इनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश हुए। लोकसभा में आए बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे मुद्दों से जुड़े हैं। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद अब 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। केवल भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल अभी दोनों सदनों से पास नहीं हुआ है। राज्यसभा में पेश किए गए दोनों बिल भी लोकसभा से पास हो चुके हैं।

खड़गे ने कहा...हल्द्वानी में मेरे जाने के बाद स्टेज का शुद्धिकरण किया

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा...'मैं हल्द्वानी में था,जहां मैंने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। वहां लाखों लोग मौजूद थे। उस समय मैंने किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया, बल्कि सिर्फ सरकार के मुद्दों को दोहराया। लेकिन मेरे भाषण के बाद बीजेपी के लोगों ने वहां उस मंच को 'शुद्ध' करने के लिए हवन किया।'

रिजिजू बोले...सरकार चर्चा चाहती है और विपक्ष बहस से भाग रहा है...

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मानसून सत्र चर्चा की नजर से अच्छा नहीं रहा। पहली बार ऐसा देखा गया है,जब सरकार संसद में चर्चा चाहती है और विपक्ष बहस से भाग रहा है।

'जल्दी आओ सदन के अंदर',हाथों में टेडी और बंदर लेकर विपक्ष ने संसद परिसर में की नारेबाजी

संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में खिलौना बंदर और टेडी लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा की अगुवाई में सांसदों ने नारेबाजी करते हुए सरकार पर छात्रों के मुद्दे पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान '56 इंच का छोटा बंदर,जल्दी आओ सदन के अंदर' का नारा लगाया गया। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन अलग अंदाज में नजर आया। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा की अगुवाई में विपक्षी सांसद हाथों में खिलौना 'बंदर' और टेडी लेकर संसद परिसर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा,'56 इंच का छोटा बंदर,जल्दी आओ सदन के अंदर। 'प्रदर्शन में महिला और पुरुष सांसद दोनों शामिल रहे। विपक्षी सांसदों ने इस प्रदर्शन के जरिए सरकार और प्रधानमंत्री पर सदन में आकर जवाब देने का दबाव बनाने की कोशिश की। यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ जब पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच लगातार गतिरोध बना रहा। विपक्ष ने इस दौरान अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने का अवसर दिए जाने की मांग भी उठाई। इन मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप के चलते कई विधायी कामकाज भी हंगामे के बीच आगे बढ़े।

झारखंड के छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन

झारखंड के छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा सांसदों ने गुरुवार को संसद भवन परिसर स्थित मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में सांसदों ने छात्रों के साथ कथित अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। भाजपा ने कहा कि छात्रों की न्याय की लड़ाई अब राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं है और पार्टी उनकी आवाज संसद तक पहुंचा रही है। खगोलशास्त्र इस दौरान साहू ने कहा कि झारखंड में पिछले 20 दिनों से छात्र आंदोलनरत हैं। यहां कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है और सात सालों से कांग्रेस, झामुमो द्वारा नौकरियों को बेचा जा रहा है। राहुल गांधी में थोड़ी भी नैतिकता है तो उन्हें दिल्ली से ट्वीट-ट्वीट खेलने की बजाय झारखंड आकर छात्रों-युवाओं से बात करनी चाहिए। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन सरकार से उन्हें दो टूक बात करनी चाहिए कि छात्रों की सीबीआई जांच की मांग को सरकार अविलंब पूरी करे। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो सरकार से समर्थन वापस लेकर उन्हें छात्रों के साथ अनशन पर बैठना चाहिए। साहू ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो झारखंड के युवाओं के हक अधिकार को छीनने का काम कर रही है।

देश में लोगों को बोलने से रोका जा रहा हमारा काम आवाज बुलंद करना : राहुल

नई दिल्ली,13 अगस्त 2026। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सरकार लोगों को अपनी बात रखने से रोक रही है। सरकार व्यवस्था लागू करना चाहती है, जबकि कांग्रेस का काम भारत को अपनी बात कहने का मौका देना है। दिल्ली में हो रहे कांग्रेस का 'रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ' के अधिवेशन में राहुल ने कहा कि जंतर-मंतर पर छात्र अपनी बात रखना चाहते थे। छात्र परेशान थे और अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। सरकार को समझ आ गया है कि लोग अब चुप नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी कोशिशें सरकार को परेशान कर सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी रात में सो नहीं पाते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कभी चाणक्य और सरदार पटेल जैसे नामों से जोड़ा जाता था,लेकिन अब वह संसद में प्रवेश तक नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार उन्हें भारत की आवाज और उसकी अभिव्यक्ति का सामना करना पड़ रहा है। भारत में बहुत से लोग कायरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहे हों और डर लगने की बात कहें तो समझ में आती है,लेकिन आज आप उन मसखरों और जोकरों से लड़ रहे हैं, जिन्हें

हमारे दर्शन या इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। यदि किसी दिन आरएसएस की अभिव्यक्ति को खत्म करने की बात होगी तो वह उसकी भी रक्षा करेंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम की कूटनीति विदेशी नेताओं को गले लगाने से कुछ ज्यादा ही जुड़ी हुई है। मुझे नहीं पता कि उन्हें यह विचार कहां से आया। उन्हें लगता है कि गले लगाना ही विदेश नीति है। ऐसा कहते हुए राहुल ने मंच पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगा लिया। वहीं,दीक्षित ने चुटकी लेते हुए कहा...आपने मुझे मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा था?' राहुल ने जवाब दिया...मैं अभी वहां तक नहीं पहुंचा हूं। उनकी इस बात से लोग हंस पड़े।

असम-अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव...सीमा पर फिर भड़की हिंसा,आमने-सामने आए दोनों राज्यों के लोग

नई दिल्ली,13 अगस्त 2026। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने गुरुवार को शीर्ष अदालत का रुख करते हुए हाई कोर्ट के उस निर्देश पर सवाल उठाया है, जिसमें मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय से कराने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर अब 17 अगस्त को सुनवाई होगी।

तीन जजों की पीठ करेगी मामले की सुनवाई : राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। अब 17 अगस्त को होने वाली सुनवाई में राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के आधार पर दलीलें रखी जाएंगी।

भाजपा कार्यकर्ता के आरोपों पर शुरू हुआ मामला

यह मामला भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत और आरोपों से जुड़ा है। शिशिर ने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में कहीं अधिक संपत्ति है। इसी शिकायत के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच एजेंसियों से आरोपों की जांच और सत्यापन कराने का निर्देश दिया था। हालांकि राहुल गांधी ने इन आरोपों के आधार पर शुरू हुई प्रक्रिया पर सवाल उठाया है।

सीबीआई और ईडी को जांच का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने जांच एजेंसियों से आरोपों का सत्यापन करने और जांच में हुई प्रगति से अदालत को अवगत कराने को कहा था। राहुल गांधी ने अब इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका में शिकायत के आधार पर आगे बढ़ाई गई कार्रवाई की वैधता पर भी सवाल उठाए गए हैं। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष एक अलग मांग भी रखी है। उन्होंने कथित आय से अधिक संपत्ति मामले की कार्यवाही को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। इस मांग के पीछे उनके कानूनी पक्ष और मामले की कार्यवाही से संबंधित विभिन्न आधार बताए गए हैं।

दो दोस्तों की हत्या कर मंदिर परिसर में दफनाया...ऊपर से लगाई टाइल्स, पुजारी पर खौफनाक कांड का आरोप

बागपत,13 अगस्त 2026। यूपी के बागपत में एक मंदिर के भीतर ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. करीब 20 दिन से लापता दो जिगरी दोस्तों की लाशें मंदिर परिसर में बने धूनी के नीचे गड्ढा खोदकर दफन मिली हैं। दोनों दोस्तों की पहचान अंकित और इसरार के रूप में हुई है। अंकित हिंदू था, जबकि इसरार मुस्लिम। दोनों की हत्या करने के बाद शवों को मंदिर परिसर में ही छिपा दिया गया और ऊपर से इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाकर जगह को ढक दिया गया। शुरुआती जांच में दोनों की हत्या अवैध संबंध के चलते की गई है,

जिसे मंदिर के पुजारी ने अंजाम दिया है। दरअसल, मामला बागपत के थाना चांदीनगर क्षेत्र के लहचौड़ा गांव स्थित गणेश मंदिर का है। बताया जा रहा है कि अंकित और इसरार करीब 20 दिन पहले घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद दोनों वापस नहीं लौटे। परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे थे। परिजनों के अनुसार, दोनों दोस्त लहचौड़ा गांव स्थित गणेश मंदिर में पुजारी से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद दोनों का कोई पता नहीं चला। लगातार तलाश के बीच परिजनों को बीती रात मंदिर परिसर में ही दोनों दोस्तों के शव दफन किए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गड्ढा खुदवाया तो वहां से दोनों के शव बरामद हुए। दोनों शवों को बाहर निकालकर पुलिस ने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि दोनों शवों को मंदिर परिसर में बने धूनी के नीचे गड्ढा खोदकर दफन किया गया था। इसके बाद उस जगह को इंटरलॉकिंग टाइल्स से ढक दिया गया, ताकि किसी को शक न हो। करीब 20 दिन बाद दोनों शवों के मिलने से मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। परिजनों ने जिस पुजारी पर हत्या का शक जताया है, उसके बारे में बताया कि वह पहले अंकित और इसरार के गांव सिंगोली तगा स्थित मंदिर में रहता था। करीब छह महीने पहले ही वह लहचौड़ा गांव के गणेश मंदिर में रहने आया था। परिजनों का आरोप है कि दोनों दोस्त पुजारी से मिलने मंदिर पहुंचे थे और इसके बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए।

पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला,नांदेड़ में गुरुद्वारे के पास हुई घटना

अमृतसर,13 अगस्त 2026। नांदेड़ में पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार को हमला हुआ। घटना सुबह करीब 11:30 बजे माता साहिब गुरुद्वारा इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक,बादल तख्त श्री हजूर साहिब जा रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति उनके पास आया और धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। हमले में उनके हाथ में चोट आई। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया।

सुरक्षाकर्मी ने हमलावर को रोका : हमले के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने तुरंत बीच-बचाव किया। इस दौरान सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गया। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस हमले की वजह और आरोपी से पूछताछ कर रही है।

हरसिमरत कौर भी साथ थीं: हमले के समय सुखबीर बादल की पत्नी और अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल भी उनके साथ थीं। इससे पहले दोनों ने नांदेड़ में तख्त श्री हजूर साहिब के दर्शन किए थे। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बादल के हाथ पर कपड़ा बंधा नजर आ रहा है।

बीजेपी ने की हमले की निंदा

पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पवित्र धार्मिक स्थल पर हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और बादल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कारोबारी नाहटा और भंसाली से जुड़े ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई

रायपुर,13 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गुरुवार तड़के प्रवर्तन विभाग (ईडी) की टीम ने तीन ठिकानों पर जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक भोपाल और रायपुर से पहुंची ईडी की अलग-अलग टीमों ने शहर से लगे तीन स्थानों पर कार्रवाई शुरू की।बताया गया है कि यह कार्रवाई जिला खनिज न्यास निधि(डीएमएफ घोटाला) मामले से जुड़े वित्तीय लेन-देन को लेकर की गई है। ईडी के अधिकारियों द्वारा सत्यम विहार कॉलोनी स्थित यश नाहटा और रोमिल नाहटा के निवास व व्यावसायिक परिसरों पर जांच की जा रही है। कामठी लाइन

स्थित कारोबारी मनीष भंसाली के 'भंसाली किराना भंडार' से जुड़े ठिकानों पर भी टीम रिकॉर्ड खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी सुबह करीब 6 बजे राजनांदगांव पहुंचे और इसके बाद संबंधित परिसरों में जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की।

जेपीएससी-जेएसएससी छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी,सीबीआई जांच की मांग पर अड़े

रांची,13 अगस्त 2026। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन गुरुवार को 20वें दिन भी जारी रहा। छात्र धरना स्थल पर डटे हैं। कई छात्र भूख हड़ताल पर हैं। लंबे समय से अनशन के कारण कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बावजूद छात्रों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। लगातार प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। धरना स्थल से करीब ढाई किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री आवास के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। प्रमुख रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है,ताकि प्रदर्शनकारी आवास की ओर आगे न बढ़ सकें। बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था का असर यातायात पर भी पड़ा है। कांके की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग रही है। कई स्थानों पर ट्रैफिक धीमा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। इससे पहले छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी थी। अब 20 दिनों से जारी आंदोलन को लेकर प्रशासन सतर्क है।

अंबाला में सिखों-किसानों और पुलिस में टकराव...सिख नेता पर हमला करने वालों को छोड़ने पर अड़े,डीएसपी का अंगूठा कटा,7 पुलिसवाले आईसीयू में...

अंबाला,13 अगस्त 2026। हरियाणा के अंबाला में प्रदर्शन कर रहे सिख और किसान गुरुवार शाम को पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शनकारी पंजाब के खालिस्तान विरोधी नेता गुरसिमरन सिंह मंड पर अंबाला में ही कुछ दिन पहले हमला करने वालों को छुड़वाने की मांग पर अड़े थे और दोपहर 1 बजे से दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर रखा था। पुलिस ने देर शाम जब हाईवे खुलवाने की कोशिश की तो दोनों पक्ष भिड़ गए। इस टकराव में अंबाला के एक डीएसपी वीरेंद्र का अंगूठा कट गया और 7-8 पुलिसवालों को गंभीर चोटें आईं। इन सभी को अंबाला के

एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज के साथ आंसूगैस के गोले छोड़े मगर भीड़ नहीं हटी। अंबाला पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, टकराव में पुलिसवालों के अलावा कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं। इससे पहले, गुरुवार सुबह सिख जत्थेबंदियों और किसानों ने मंड पर एफआईआर दर्ज करने और उन पर हमला करने वालों को छोड़ने की मांग करते हुए दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर डेरा जमा लिया। अंबाला रेंज के ढूल पंकज नैन और एसपी अजीत शेखावत ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली से पंजाब-चंडीगढ़ और पंजाब-चंडीगढ़-हिमाचल की ओर जाने वाले वाहनों को अन्य रूट पर डायवर्ट कर दिया। देर शाम पुलिस ने मंड पर एफआईआर दर्ज कर ली मगर प्रदर्शनकारी जेल में बंद अपने दो साथियों को रिहा करने पर अड़े रहे। रात करीब 9 बजे जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो दोनों पक्ष भिड़ गए।

संपादकीय

विदेशी पूंजी आकर्षित करने की चुनौती

पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक पूंजी और व्यापार के लिए अधिक आकर्षक एवं भरोसेमंद गंतव्य बनाने के साथ ही आफशोर इन्वेस्टमेंट फंड्स और फंड प्रबंधकों के लिए नियमों को सरल बनाना है। देखा जाए तो यह भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने, कर व्यवस्था में स्पष्टता लाने और घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ बनाने के परिप्रेक्ष्य में एक अत्यंत अहम कदम है। विदेशी पूंजी के प्रवाह में वृद्धि से देश की आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी और बाहरी आर्थिक झटकों को सहने की क्षमता बढ़ेगी।

भारत विदेशी पूंजी आकर्षित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल में लागू आरबीआइ की नई रियायती स्वैप सुविधा को वैश्विक स्तर पर व्यापक समर्थन मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना और भुगतान संतुलन को मजबूत करना है। इस योजना के तहत बैंकों को जिन तीन प्रमुख माध्यमों से विदेशी मुद्रा जुटाने में मदद मिली है,उनमें प्रमुख रूप से विदेश से ली जाने वाली जमा योजनाएं, विदेशी मुद्रा ऋण और बाहरी वाणिज्यिक उधार शामिल हैं।

इस समय भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की वापसी के भी स्पष्ट संकेत देखने को मिल रहे हैं। लंबे समय तक बिकवाली के बाद विदेशी निवेशक एक बार फिर भारत जैसे स्थिर और सुरक्षित बाजारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके प्रमुख कारणों में रुपये की स्थिरता,कंपनियों की बेहतर आय,भू-राजनीतिक चिंताओं में कमी और दीर्घकालिक निवेश के बेहतरीन अवसर शामिल हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 682 अरब डालर से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों का विश्वास बढ़ा है,वैश्विक ऋण भुगतान एवं प्रबंधन आसान हुआ है और घरेलू बाजार में महंगाई को नियंत्रित रखना संभव हुआ है।

वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के बाद आर्थिक सुधारों का नया दौर शुरू किया गया। तब से अब तक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निरंतर कई ठोस कदम उठाए गए हैं। बीमा, दूरसंचार और खुदरा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक कर दी गई है। रक्षा क्षेत्र में भी कुछ शर्तों और नियमों के साथ 100 प्रतिशत एफडीआइ की अनुमति दी गई है। अधिकांश क्षेत्रों में पूर्व-सरकारी अनुमति के बिना (स्वचालित मार्ग से) निवेश करने की छूट प्रदान की गई है। पुराने और कठोर फेरा कानून को समाप्त कर लचीला फेमा लागू किया गया है,जिससे विदेशी मुद्रा का प्रवाह और लेनदेन आसान हो गया है।

देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने और विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया है। निवेशकों को कर में छूट,सरल नियम और आधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का विकास किया गया है। प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआइ) जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। व्यापार को गति देने के लिए चालू खाते पर रुपये को पूरी तरह से परिवर्तनीय बनाया गया है तथा भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत और पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) के लिए नियमों को सरल किया गया है। विभिन्न बहुआयामी प्रयासों के बावजूद भारत में टिकाऊ विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए अभी भी कई ठोस सुधारों की आवश्यकता है। केवल बड़े घरेलू बाजार और उच्च विकास दर के भरोसे रहना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए देश के नियामक ढांचे, कर प्रणाली और कानूनी तंत्र में व्यापक बदलाव अनिवार्य हैं। दीर्घकालिक निवेश के लिए स्थिर नीतियां पहली प्राथमिक शर्त हैं। कर नियमों, सीमा शुल्क और क्षेत्र-विशेष के प्रविधानों में अचानक होने वाले परिवर्तनों से निवेशक दूर भागते हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न स्वीकृतियों, अनुमतियों और जटिल नियमों का बोझ अभी भी बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में विवाद समाधान की धीमी गति और अनुबंधों को लागू करने में होने वाली देरी विदेशी पूंजी के प्रवाह में बड़ी बाधा बनती है।

निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का नियंत्रण और मुद्रास्फीति को संतुलित सीमा में रखना जरूरी है। भारतीय मुद्रा के मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव निवेशकों के रिटर्न को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है। यद्यपि भारत का शेयर बाजार मजबूत है,पर कारपोरेट ऋण बाजार अभी भी सीमित है। इसे अधिक विस्तृत और तरल बनाना पोर्टफोलियो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनिवार्य है। पूंजी की आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों को कम करके इसे अधिक लचीला बनाना होगा। चीन पर अपनी निर्भरता कम करने (चाइना प्लस वन) की इच्छुक वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए केवल उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनाएं ही पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे, परिवहन लागत में कमी और कुशल कार्यबल का एक एकीकृत ढांचा तैयार करना होगा।

देशवासियों को चाहिए समग्र स्वतंत्रता

आत्माराम यादव
नर्मदापुरम,
मध्यप्रदेश

प्रकाशक: दैनिक घटती-

आज भी हमारी स्वतंत्रता अपूर्ण कही जा सकती है। स्व तंत्रता केवल भौगो लिक नहीं होती है, यह मानसिक भी होती है और आज भी हम मानसिक रूप से परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। हमने राजनैतिक स्वतंत्रता तो अवश्य प्राप्त ली है परन्तु मानसिक स्वतंत्रता या मानसिक आजादी हमें आज तक हासिल नहीं हो पाई है। क्या हमने सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है? वास्तविकता यही है कि हमारी मानसिक गुलामी या मानसिक दासता के कारण हमारी स्वतंत्रता आधी-अधूरी है। देश को मिली आजादी के बाद देशवासी आज भी मानसिक गुलामी से मुक्त नही हुए है और इसलिए उन्होंने स्वदेशी के प्रति जितना लगाव नहीं उससे कही ज्यादा वे अंग्रेजियत की यहाँ छोड़ी परपराओं, वेशभूषाओं,भाषा,उनकी शिक्षा प्रणाली, न्याय प्रणाली और उनके बनाये गये कानूनों आदि से प्रेम करते है और उन्हें ही श्रेष्ठ मानते आ रहे है । महाराष्ट्र जैसे कई प्रदेश मातृभाषा हिंदी के प्रति नफरत से भरे है फिर कैसे कह सकते है की अन्य प्रदेशवासी अपने ही देश में स्वदेश परम्पराओं, वेशभूषाओं, भारतीय लिपि (देवनागरी लिपि) भारतीय भाषाओं, भारतीय शिक्षा प्रणाली,चिकित्सा प्रणाली, न्याय प्रणाली तथा अन्य सभी भारतीय वस्तुओं को हेय अथवा कमतर मानने की भावना से खुद को मुक्त रखे हुए है, ये सभी आज आजाद देश में खुद को मानसिक गुलामी या मानसिक दासता से मुक्त नहीं कर सके है।

दो सौ सालों तक अंग्रेज हमारा मानसिक,सांस्कृतिक,राजनीतिक एवं आर्थिक शोषण किया करते थे इसलिए हम भारतीय अंग्रेजों से नफरत करते थे और उनको भारत से बाहर भगाना चाहते थे। हम लोग अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में भले ही सफल हो गये हों परन्तु तब भी वर्तमान में वे ही तौर तरीके अपनाये जा रहे हैं जो कि अंग्रेजों द्वारा अपनाये जाते थे। शासन एवं प्रशासन में भारतीय लोग कलेक्टर,पुलिस अधीक्षक बन कर आ अवश्य गये हैं परन्तु उनके अधिकांश कार्यशैली अंग्रेजों के समान होने के कारण वे भी अंग्रेजों की तरह ही प्रतीत होते हैं। बस अंतर केवल इतना ही लगता है कि वे गोरे अंग्रेज थे और ये काले अंग्रेज हैं।

विश्व के जिन देशों ने दूसरे देशों से स्वतंत्रता प्राप्त की उनमें से कुछ देशों ने स्वतंत्रता हासिल करने के तत्काल बाद शासक देशों की परपराओं, संस्कृतियों,भाषाओं,खान-पान व रहन-सहन आदि को छोड़कर अपने-अपने देशों की परपराओं,संस्कृतियों, भाषाओं को अपना लिया,किन्तु भारतीय राजनेताओं ने स्वतंत्रता के 78 साल बीत जाने के बाद भी अंग्रेजों की अधिकांश परपराओं,वेश-भूषाओं, खान-पान व रहन-सहन,उनकी भाषा,उनकी लिपि (रोमन लिपि) को नहीं छोड़ा है।

यह अलग बात है की वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार ने अंग्रेजों के बनाए कानून से देशवासियों को मुक्ति दिला कर भारतीय कानून लागू कर दिए किन्तु न्यायालयों में वकीलों-जजों द्वारा पहने जाने वाली वेशभूषा काला कोट-गाउन आदि के साथ दी जाने वाली उपमाओं-उपाधियों से स्वतंत्रता प्राप्त नही कर सके है और अंग्रेजों के पैटर्न को अपनाकर मानसिक गुलामी को जीने को विवश है। आज तक कुछ चीजें एवं कार्य ऐसे अवश्य हो सकते हैं जो कि विश्व के सभी देशों के नागरिकों के लिए उपयोगी तथा सार्थक हों,परन्तु सभी चीजें एवं सभी कार्य सभी देशों के नागरिकों के लिए उपयोगी तथा सार्थक कदापि नहीं हो सकते हैं। इंग्लैण्ड तथा यूरोप के ठण्डे देशों में टाई बाँधना उपयुक्त हो सकता है लेकिन भारत जैसे देश में सभी मौसमों में टाई बाँधना उचित नहीं जान पड़ता है जबकि अपनी मानसिक गुलामी के कारण हमारे ही कुछ लोग टाई बांधने में गर्व महसूस करते हैं। हमारे विश्व विद्यालयों में काले चोगे पहनकर डिग्रियाँ बंटवाई जाती हैं। अदालतों में काले चोगे धारण करके बहसें करवाई जाती हैं। प्रकाश की ज्योति बुझाने को हमारे देश में अपशकुन माना जाता है परन्तु हम लोग बहुत गर्व के साथ मोमबत्तियां बुझाकर तथा केक काटकर अपने बच्चों के जन्म दिवस मनाकर अंग्रेजी मानसिकता से मुक्त नही हो सके हैं।आज भले ही वर्तमान मोदी सरकार ने अंग्रेजों द्वारा बनाये गये कानूनों को हटा दिया किन्तु पुलिस थानों में कार्यवाही में हम यथावत उन कानूनों के अपनाये जाने की आदतों से मुक्त नहीं हो सके और भारतीय कानूनों में उनके भय से आज भी जनता त्रस्त है।

हम स्कूल-कालेजों में अंग्रेजों द्वारा लिखवाये गये व् आजादी के बाद मुस्लिम वर्ग से बनाये गए शिक्षामंत्री के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हुमायूँ कबीर जी, एमसी छागला और फकरुद्दीन अली अहमद आदि के कारण सनातन धर्म के इतिहास से वंचित रहे और देशवासिओं पर अत्याचार कर चोर लुटेरे के रूप में हिन्दू राजाओं पर हमला कर, मंदिरों को नष्ट कर मुग़ल धर्म को प्रतिष्ठित करने वाले मुस्लिम आक्रान्ताओं को महान बनाने वाले झूठे और भ्रामक इतिहास को पढ़ाया जाने लगा जिसे छात्र आज भी पढ़ रहे है और सनातन धर्म, रामायण, गीता, महाभारत के इतिहास से वंचित है। अब तो देश को नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला है क्या वे आजाद भारत की आने वाली पीढ़ी को लॉर्ड मैकाले द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली को जमी में दफ़न कर ऋषि-गुरुकुल परम्परा को प्रतिष्ठित कर सकेंगे?

एक तथ्य यह भी विदित है कि अंग्रेजों के जमाने में भारत से कच्चा माल कौड़ियों के मोल इंग्लैण्ड भिजवाया जाता था और इंग्लैण्ड से तैयार माल अत्यन्त ऊँचे दामों पर भारत में लाया जाता था। आज वैश्विकरण के युग में भले अमेरिका इस परम्परा को थोपकर आर्थिक गुलामी की और ले जाने के लिए दबाव डाल रहा है और देश किसी भी स्थिति में उसका मुकाबला कर उसके मुह पर करारा तमाचा जड़कर विश्व के मानचित्र पर मजबूती से खड़ा है,क्या भारत से अंग्रेजों के चले जाने के बावजूद भारत का आर्थिक शोषण जारी करने वाली मैकाले की शिक्षा प्रणाली से हमे स्वतंत्रता नही मिलेगी?

विश्व के कुछ देशों की प्रभावशाली महिलाएं सोशल मीडिया की मदद से भारतीय महिलाओं से सलाह माँगती हैं कि वे अमुक अवसर पर कौन सी साड़ी पहने परन्तु अपनी मानसिक दासता के कारण कुछ भारतीय महिला अंग्रेज महिलाओं जैसे वस्त्र धारण करने में गर्व महसूस करती हैं। संपूर्ण विश्व के विद्वान एवं भाषाविद् भारत की देवनागरी लिपि को एक वैज्ञानिक एवं विकसित लिपि मानते हैं,परन्तु मानसिक गुलामी की भावना से ग्रसित हमारे ही कुछ लोग रोमन लिपि को एक सरल,विकसित तथा उपयोगी लिपि मानते हैं। इसलिए आजकल हमारे देश के कुछ लोग अपने मोबाइल फोनों,लैपटॉपों से अपने अधिकांश संदेश (मैसेज) रोमन लिपि में ही लिखते हैं। अपनी सरलता एवं वैज्ञानिकता के कारण हमारी हिन्दी भाषा संपूर्ण विश्व में तेजी के साथ पनप रही है परन्तु हमारे देश के कुछ लोग आज भी हिन्दी को अविकसित तथा अनुपयोगी भाषा मानते हैं,यह वोटों की राजनीति नही तो क्या है?

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, संसद, केंद्रीय शासन,केन्द्रीय प्रशासन एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आज भी अंग्रेजी का ही बोलबाला है। स्वदेशी को अपनाने के ढोंग तो बहुत किये जाते हैं परन्तु स्वदेशी को कुचलने के लिए सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। भारत में जब तक अंग्रेजों की परपराएँ,उनकी भाषा अंग्रेजी और उनके अधिकांश तौर-तरीके चलते रहेंगे तब तक यह स्वीकार करने में मानसिक कष्ट होता रहेगा कि हम आजाद हो गये हैं। कोई यह तो बताये कि क्या हम वास्तव में आजाद या स्वतंत्र हो गये हैं? सच्ची आजादी तो तभी हासिल हो पायेगी जब हम अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी,उनकी गलत परपराओं,निरर्थक वस्तुओं की आवश्यकता जतलाकर व्यापार कर जबरिया थोपने वाली कंपनियों को विदा कर सके और देशवासियों को ठगने लुटने से रोक सके? जन-जन की भाषा हिन्दी, भारतीय परपराओं और संस्कृति, सभ्यता को हम अपनाने के साथ सनातन धर्मानुगत परिष्कृत वेद पुराणों उपनिषदों की परा-अपरा जगत की शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करा कर अपने मौलिक विचारों, मान्यताओं और मूल्यों की स्थापना कर सके तथा दूसरों के दिखाए रास्ते से जिस प्रकार अब तक मंजिल की प्राप्ति संभव न होने से वंचित रहे है,उससे स्वतंत्र हो सके ताकि अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति के साथ हम समग्र स्वतंत्रता प्राप्त कर सके।

सावन की रिमझिम और बारिश का जादू,प्रकृति का नया श्रृंगार

सृजन और भावनाओं का मिलन

साहित्यकारों, कवियों और प्रेमियों के लिए बारिश हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रही है। रिमझिम फुहारों के बीच बैठकर लिखना,पढ़ना या संगीत सुनना इस मौसम के सबसे खूबसूरत पहलू हैं। बारिश केवल प्रकृति की प्यास नहीं बुझाती,बल्कि यह इंसानी मन के भीतर दबी संवेदनाओं और भावनाओं को भी सींचती है।बारिश का यह मौसम हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी तपी हुई धूप (कठिनाइयाँ) क्यों न आएं, एक न एक दिन राहत की फुहारें जरूर बरसती हैं। यह हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का संदेश देता है। तो इस खूबसूरत बारिश में, खिड़की से बाहर देखिए, प्रकृति के इस अद्भुत रूप को महसूस कीजिए और अपने भीतर के लेखक या कलाकार को थोड़ा सा वक्त दीजिए।

डॉ. मुश्ताक अहमद
हरदा,मध्यप्रदेश

आसमान में घिरे काले-घने बादल, ठंडी हवाओं के झोंके और सोंधी खुशबू के साथ जब बारिश की बूंदें धरती पर उतरती हैं,तो पूरा वातावरण जीवंत हो उठता है। बारिश का मौसम केवल मौसम में बदलाव नहीं है, बल्कि यह भावनाओं,कविताओं और प्रकृति के उत्सव का दूसरा नाम है। जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही हो, तो यह समय थम सा जाता है और मन किसी अनजाने सुकून में डूब जाता है।

प्रकृति का कायापलट और हरियाली की चादर

गर्मी की तपिश से झुलस चुकी धरती को जब सावन की पहली फुहार मिलती है, तो वह पुनर्जीवित हो उठती है। पेड़-पौधों के पत्तों पर जमी धूल धुल जाती है और वे चमक उठते हैं। सूखी घास और बंजर ज़मीन पर हरियाली की एक लंबी चादर बिछ जाती है। मिट्टी से उठने वाली सोंधी खुशबू इस मौसम का सबसे जादुई अहसास होती है, जो सांसों में भरते ही रूह को तरोताज़ा कर देती है।

ठहर सा जाता है जीवन का शोर

बारिश के दिनों में शहर की भागदौड़ भरी रफ़्तार कुछ पल के लिए धीमी पड़ जाती है। खिड़की के पास बैठकर गिरती हुई बूंदों को देखना, चाय की गरम चुस्की लेना और बारिश की रिमझिम धुन सुनना,अपने आप में एक मेडिटेशन जैसा अनुभव है। यह मौसम हमें अपनी व्यस्त ज़िंदगी से थोड़ा वक्त निकालकर खुद के साथ जुड़ने का मौक़ा देता है। पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं और मन में अनजाने ही कल्पनाओं के नए पंख लग जाते हैं।

फनकारों के संस्कारों का आईना...

संजय एम
तराणेकर
इन्दौर,
मध्यप्रदेश

वो नसीर हों या अनुपम,
कला के अपने रंग हैं,
कंगना की अपनी बेबाकी,
सबके अपने ढंग हैं।
कलाकार की पहचान
केवल पर्दे से नहीं होती,
शब्दों की मर्यादा में भी
उसकी तस्वीर पिरोती।

अनुपम ने मंच सजाया,
नसीर किरदार निभाए,
कंगना ने बेबाक शब्दों से
अपने विचार बताए।
मतभिन्नता हों ग़म नहीं,
लोकतंत्र में मतभेद रहें,
यूं संवाद की भाषा में
सम्मान के कुछ शब्द रहें।

नाम बड़े, कला बड़ी हो,
तो जिम्मेदारी भी बड़ी,
शब्द किसी के दिल तोड़ें,
उपलब्धि लगे अधूरी।
जन्म से मिले संस्कारों का
असर कहीं आता है,
इंसान यहाँ कर्मों से ही
अपना परिचय पाता है।

भले शाह हों या हो खेर,
रनौत हों या कोई और,
कला माध्यम बने,न हो
विचारों में जंग का शोर।
फ़नकार वही जो
असहमति भी सम्मान से कहें,
अपने शब्दों से समाज में
घृणा नहीं,संवाद बहें।

हौसले की उड़ान उम्र की सीमाओं से परे

डॉ. विजय गर्ग
मलोट,पंजाब

अक्सर उम्र को किसी व्यक्ति की क्षमता का पैमाना मान लिया जाता है। समाज सामान्यतः यह मानता है कि सपने देखने,सीखने,नवाचार करने और उपलब्धियाँ हासिल करने का सबसे उपयुक्त समय युवावस्था है, जबकि वृद्धावस्था को धीमा पड़ने और पीछे हटने का समय समझा जाता है। लेकिन इतिहास और दैनिक जीवन की असंख्य घटनाएँ इस धारणा को गलत साबित करती हैं। बार-बार लोगों ने यह सिद्ध किया है कि सफलता का वास्तविक आधार उम्र नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प,जुनून और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का साहस है। उम्र केवल वर्षों की गिनती करती है, जबकि हौसला जीवन की दिशा तय करता है।

जीवन का प्रत्येक चरण अपने साथ अनूठे अवसर लेकर आता है। बचपन जिज्ञासा का समय है, युवावस्था खोज और प्रयोग का,प्रौढ़ावस्था जिम्मेदारियों का और वृद्धावस्था अनुभव से प्राप्त बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इनमें से कोई भी चरण दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। प्रत्येक अवस्था व्यक्ति के विकास और समाज में योगदान देने के लिए अलग-अलग आधार प्रदान करती है। जो लोग सीखना, स्वयं को बदलना और चुनौतियों को स्वीकार करना कभी नहीं छोड़ते,वे यह अनुभव करते हैं कि जीवन हर उम्र में नई संभावनाओं से भरा हुआ है।

इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है,जहाँ लोगों ने उस उम्र में असाधारण उपलब्धियाँ हासिल कीं, जिसे समाज उनकी सर्वश्रेष्ठ उम्र से आगे मानता था। अनेक लेखकों ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में महान कृतियों की रचना की,वैज्ञानिकों ने सेवानिवृत्ति के बाद भी महत्वपूर्ण शोध किए,उद्यमियों ने साठ और सत्तर वर्ष की आयु में सफल व्यवसाय स्थापित किए तथा खिलाड़ियों ने अपेक्षाओं से कहीं अधिक समय तक सक्रिय रहकर लाखों लोगों को प्रेरित किया। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि दृढ़ निश्चय कभी सेवानिवृत्त नहीं होता।

आधुनिक युग ने वृद्धावस्था के अर्थ को बदल दिया है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं,संतुलित पोषण और बढ़ती औसत आयु ने लोगों को पहले की तुलना में अधिक समय तक सक्रिय और स्वस्थ रहने का अवसर दिया है। आज सेवानिवृत्ति केवल नौकरी का अंत नहीं, बल्कि जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। अनेक लोग इस समय का उपयोग समाज सेवा, अध्यापन,लेखन,यात्रा, उद्यमिता और वर्षों से अधूरे पड़े सपनों को पूरा करने में कर रहे हैं। आज अनेक वरिष्ठ नागरिक डिजिटल तकनीक सीख रहे हैं,ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और समाज में सार्थक योगदान दे रहे हैं–ऐसी बातें जो कुछ दशक पहले कल्पना से परे थीं।

साथ ही,केवल युवा होना सफलता की गारंटी नहीं है। अनेक युवाओं में ऊर्जा तो होती है,लेकिन कभी-कभी उनमें धैर्य,अनुशासन और स्पष्ट दिशा का अभाव होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर परिश्रम करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। कई बार एक दृढ़ निश्चयी साठ वर्षीय व्यक्ति, लक्ष्यहीन बीस वर्षीय युवक से कहीं अधिक उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सफलता उम्र से नहीं, समर्पण और निरंतर प्रयास से बनती है।

मनुष्य के सामने सबसे बड़ी बाधा शारीरिक वृद्धावस्था नहीं,बल्कि मानसिक सीमाएँ होती हैं।अब मैं सीखने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब बहुत देर हो चुकी है या मेरा समय निकल गया जैसी धारणाएँ व्यक्ति स्वयं अपने लिए बाधाएँ खड़ी कर लेता है। जबकि वास्तविकता यह है कि मानव मस्तिष्क जीवन भर सीखने की क्षमता बनाए रखता है। चाहे नई भाषा सीखना हो, कोई वाद्ययंत्र बजाना, नया व्यवसाय शुरू करना,पुस्तक लिखना या उच्च शिक्षा प्राप्त करना–जब तक जिज्ञासा और दृढ़ इच्छाशक्ति जीवित है, तब तक विकास की संभावनाएँ भी जीवित रहती हैं।

समाज की भी यह जिम्मेदारी है कि वह वृद्धावस्था को देखने का अपना दृष्टिकोण बदले। अक्सर वरिष्ठ नागरिकों को केवल देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों के रूप में देखा जाता है, जबकि वास्तव में वे अनुभव, व्यावहारिक ज्ञान और भावनात्मक परिपक्वता का अनमोल भंडार होते हैं। वे उत्कृष्ट मार्गदर्शक,शिक्षक,स्वय सेवक और सामुदायिक नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं। यदि उन्हें सक्रिय भूमिका निभाने के अवसर दिए जाएँ, तो पूरा समाज उनके अनुभवों का लाभ उठा सकता है।

इसके साथ-साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार,निरंतर अध्ययन, सार्थक सामाजिक संबंध और सकारात्मक सोच स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन की आधारशिला हैं। ये आदतें व्यक्ति को ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और उत्पादक बनाए रखती हैं तथा यह सिद्ध करती हैं कि केवल बढ़ती उम्र किसी की क्षमता को सीमित नहीं करती।

शायद सबसे बड़ी सीख यह है कि साहस कभी बूढ़ा नहीं होता। हौसला वह शक्ति हैजो व्यक्ति को नई शुरुआत करने,अनिश्चितताओं का सामना करने, परिवर्तन को स्वीकार करने और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। यही आंतरिक शक्ति असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्यों को भी संभव बना देती है।

युवा पीढ़ी भी इस विचार से प्रेरणा ले सकती है। उन्हें असफलता से डरने या समय के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन उम्र की दौड़ नहीं,बल्कि निरंतर सीखने, स्वयं को बेहतर बनाने और आगे बढ़ते रहने की यात्रा है। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों को भी अपनी क्षमताओं को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हर नया दिन सीखने, सृजन करने और दूसरों को प्रेरित करने का एक नया अवसर लेकर आता है।

अंततः,उम्र केवल कैलेंडर पर दर्ज एक संख्या है,लेकिन हौसला वह शक्ति है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। सपनों की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती और दृढ़ संकल्प की कोई सीमा नहीं होती। जब तक मनुष्य का मन आशावान,जिज्ञासु और साहसी बना रहता है,तब तक हौसले की उड़ान उम्र की सीमाओं से परे जाती रहेगी।

आजादी हमें मिली थी, गुलामी हमने खुद चुन ली

अंग्रेज़ चले गए,मालिक हमने ही खुद बना लिए

प्रो.आर.के.जैन
बड़वानी
मध्यप्रदेश

कमाल की आज़ादी है हमारी! अंग्रेज़ों को भगाने के बाद हमने गुलामी के इतने नए दरवाज़े खोल लिए कि अब किसी विदेशी हुकूमत को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। 15 अगस्त को ध्वजारोहण होगा। राष्ट्रगान बजेगा। भाषणों में शहीदों का जिक्र होगा। तालियाँ पड़ेंगी। तस्वीरें खिंचेंगी। और फिर हम उसी दिन वापस अपनी-अपनी गुलामियों की ड्यूटी पर लौट जाएँगे।

कोई मोबाइल का गुलाम है,कोई सोशल मीडिया का;किसी की खुशी 'लाइक'से,तो किसी की हैसियत 'फॉलोअर' से तय होती है। कोई ट्रेंड के पीछे भागता है, कोई भीड़ के साथ, क्योंकि अपनी राय बनाने से आसान है दूसरों की नकल करना। कोई बाज़ार का गुलाम है–जरूरत हो या न हो, विज्ञापन कहेगा तो खरीदेंगे। कोई ब्रांड का, कोई दिखावे का, कोई किस्त और कर्ज का। जेब खाली हो सकती है, खरीदारी नहीं;घर छोटा हो सकता है, ईएमआई बड़ी होनी चाहिए।

कोई नौकरी और पद का गुलाम है,कोई पैसे का;कोई समाज क्या कहेगा का,तो कोई रिश्तेदारों की राय का। बच्चे अंकों के गुलाम हैं,युवा प्रतियोगिता और नौकरी की दौड़ के, और बड़े-बुजुर्ग अपनों के समय को तरस रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक गुलामी जाति,धर्म और राजनीति की है। हम इतने 'आज़ाद' हैं कि अपने नेता की गलती को भी सही साबित करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। सवाल पूछना देशद्रोह लगता है और आंख बंद करके समर्थन करना देशभक्ति।

अंग्रेज़ों की गुलामी में बेड़ियाँ हाथों में थीं,इसलिए गुलामी साफ दिखाई देती थी। हमारी गुलामी का अंदाज़ देखिए–जंजीरें भी अपनी,ताले भी अपने और चाबी भी अपनी;फिर भी हम इसे पसंद,सुविधा और आज़ादी कहकर गर्व से ढो रहे हैं। इस 15 अगस्त ध्वजारोहण कीजिए,तिरंगे को सलाम कीजिए,मगर एक सवाल खुद से भी कीजिए–अंग्रेज़ 1947 में चले गए, अब हमारी चुनी हुई गुलामियाँ कब जाएँगी?

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

तिरंगे की शान में सजा अंबिकापुर,भारत माता के जयकारों से गूंजा शहर

मल्टीपरपज स्कूल से गांधी स्टेडियम तक निकली भव्य तिरंगा यात्रा,देशभक्ति के रंग में रंगा शहर,बड़ी संख्या में नागरिक हुए शामिल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

स्वतंत्रता दिवस से पहले गुरुवार को 'हर घर तिरंगा'अभियान के तहत अंबिकापुर में निकली भव्य तिरंगा यात्रा ने पूरे शहर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। हाथों में तिरंगा थामे बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। भारत माता की जय,वंदे मातरम् और देशभक्ति के नारों से शहर गूंजता रहा। युवाओं से लेकर जनप्रतिनिधियों,अधिकारियों,सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने उत्साह के साथ यात्रा में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया।

मल्टीपरपज स्कूल से शुरू हुई यात्रा

तिरंगा यात्रा का शुभारंभ मल्टीपरपज स्कूल से हुआ। यहां से यात्रा महामाया चौक,घड़ी चौक और गांधी चौक होते हुए गांधी स्टेडियम मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में हाथों में लहराते तिरंगे और देशभक्ति गीतों ने माहौल को उत्साह से भर दिया। जगह-जगह नागरिकों ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में युवाओं की विशेष भागीदारी रही। बड़ी संख्या में युवा और विद्यार्थी तिरंगा लेकर आगे बढ़ते नजर आए।

तिरंगा हमारी आन,बान और शान का प्रतीक

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा देश की एकता,अखंडता और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने का आह्वान किया। मंत्री ने सभी नागरिकों से अपने घर,प्रतिष्ठान और कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील भी की।

देशभक्ति गीतों और नारों के बीच लोगों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया।

राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश : गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता और गौरव का प्रतीक है तथा इसके सम्मान की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है।

स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को याद किया : कलेक्टर अजीत वसंत ने तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे नागरिकों का स्वागत करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन आदर्शों और मूल्यों के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, वे आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों और आजादी के मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए राष्ट्रप्रेम, एकता और जिम्मेदार नागरिकता की भावना को मजबूत करना चाहिए।

जयकारों से गूंजता रहा शहर : यात्रा के दौरान 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के नारों से शहर का वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत रहा। लोगों ने उत्साहपूर्वक तिरंगा लहराया। देशभक्ति गीतों ने यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह और बढ़ा दिया। 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना रहा। यात्रा में शामिल लोगों ने देश की एकता,अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प भी लिया।

तिरंगा यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष निरुपा सिंह,नगर निगम महापौर मंजूषा भगत, निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी,भारत सिंह सिसोदिया,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल,जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल,अपर कलेक्टर सुनील नायक, एसडीएम बनसिंह नेताम सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए।

बाइक चोरी का खुलासा: एक आरोपी गिरफ्तार,3 चोरी की बाइक बरामद

बतौली,लुण्ड्रा और मणिपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई,आरोपी के साथ दो विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल

-संवाददाता-
अंबिकापुर/बतौली,13 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की तीन दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार वाहन चोरी की वारदातों में आरोपी के साथ दो विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल थे। मामले में बतौली,लुण्ड्रा और मणिपुर पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक ग्राम देवरी डुमरपारा निवासी गिरधारी किस्पोट्टा ने बतौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी-15-DE-1621 को 2 अगस्त की रात करीब 9 बजे घर के आंगन में खड़ा किया था। 3 अगस्त की सुबह करीब 5 बजे उठने पर मोटरसाइकिल गायब मिली। आसपास तलाश करने के बाद भी वाहन का पता नहीं चला। रिपोर्ट पर बतौली पुलिस ने अपराध क्रमांक 100/26, धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

नोटिस के बाद भी थाने नहीं पहुंचा संदेही : विवेचना के दौरान पुलिस को संदेही सागर कुजूर उर्फ बुतरू,निवासी बेलकोटा भगतपारा, के संबंध में जानकारी मिली। पुलिस ने उसे विवेचना में सहयोग के लिए बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत कई बार नोटिस जारी किया। परिवार के लोगों को भी उसे थाने में उपस्थित कराने के लिए समझाइश दी गई,लेकिन वह पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस टीम ने उसकी तलाश कर हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने वाहन चोरी की वारदातों में शामिल होना स्वीकार किया।

बरगीडीह और मेंड्राकला से भी चोरी किए वाहन : पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 13 जुलाई 2026 को ग्राम बरगीडीह से एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी-15-DZ-9655 चोरी की थी। इसके अलावा अपने एक साथी के साथ ग्राम मेंड्राकला,अंबिकापुर से एक्टिवा स्कूटी क्रमांक सीजी-15-EE-9186 चोरी करना बताया। इसी तरह 3 अगस्त की सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राम देवरी डुमरपारा से एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी-15-DE-1621 चोरी करने की बात स्वीकार की।

आरोपी के कब्जे से बाइक बरामद : आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने उसके कब्जे से देवरी डुमरपारा से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ और आगे की कार्रवाई में पुलिस टीम ने चोरी की कुल तीन दोपहिया वाहन बरामद किए। पुलिस ने मामले में छोटे संगठित अपराध का घटित होना पाए जाने पर धारा 112 बीएनएस तथा सामान्य आशय से अपराध किए जाने पर धारा 3(5) बीएनएस भी जोड़ी है।

सामान्य सभा में हंगामे को लेकर महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा

महापौर पर विपक्षी पार्षदों से अमर्यादित व्यवहार का आरोप,निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन,सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और जांच की मांग.....

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

नगर निगम की सामान्य सभा में कथित अमर्यादित आचरण को लेकर सियासत गरमा गई है। महापौर श्रीमती मंजूषा भगत पर विपक्षी पार्षदों के साथ व्यक्तिगत टिप्पणी करने और सदन की गरिमा के विपरीत व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। गुरुवार को महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीमा सोनी के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला पार्षदों एवं कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर पूरे घटनाक्रम की जांच और दोष पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।

वायरल ऑडियो की जांच में देरी पर उठा था सवाल

महिला कांग्रेस के अनुसार सामान्य सभा में कला केंद्र मैदान के आबंटन से जुड़े एक वायरल ऑडियो में पैसों के लेन-देन के आरोपों की जांच में कथित देरी का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने उठाया था। कांग्रेस का कहना है कि महापौर की ओर से अजाक थाना में आवेदन दिए जाने के बावजूद करीब दो माह तक जांच नहीं होने पर सदन में सवाल उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर एक माह के भीतर जांच पूरी कराने का प्रस्ताव पारित किए जाने की मांग की थी।

सवाल के जवाब के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणी का आरोप

ज्ञापन में महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय महापौर ने विपक्षी पार्षदों पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कीं,जिससे सदन का माहौल गरमा गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि महापौर आसंदी के माध्यम से जवाब देने के बजाय सीधे विपक्षी सदस्यों से उलझीं और कथित तौर पर अपनी कुर्सी छोड़कर आगे बढ़ीं। इस दौरान पानी की बोतल लहराने का भी आरोप लगाया गया है। महिला कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम को सदन की गरिमा के विपरीत बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है।

विपक्ष का सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार

महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीमा सोनी ने कहा कि विपक्ष द्वारा जनहित से जुड़े सवाल उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। सवाल का जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणी करना और सत्ता के अहंकार का प्रदर्शन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिला एवं आदिवासी होने की पहचान सम्मान का विषय है, लेकिन इसे किसी भी कथित अमर्यादित आचरण के बचाव के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मान और सदन की गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।

सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सुरक्षित रखने की मांग : महिला कांग्रेस ने निगम आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में सामान्य सभा की सीसीटीवी फुटेज एवं वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की मांग की है, ताकि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो सके। साथ ही सदन की गरिमा भंग किए जाने की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में कला केंद्र मैदान से जुड़े वायरल ऑडियो में लगाए गए पैसों के लेन-देन संबंधी आरोपों की जांच में हुई कथित देरी की भी जांच कर समयबद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।

महिला कांग्रेस ने कहा...सवाल उठते रहेंगे

सीमा सोनी ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि जनहित के सवाल पूछने पर व्यक्तिगत हमले या सत्ता का अहंकार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षद हसन खान, कलीम अंसारी,बाबर इदरीसी, शुभम जायसवाल,गीता प्रजापति,जेनेविवा कुजूर,निम्न राशि एक्का,मेघा खांडेकर,विनोद एक्का,संध्या खानी,नुजहत फातिमा,गीता रजक,मल्टी सिंह,शालिनी नंद,प्रीति सिंह, उर्मिला विश्वास,सपना सिन्हा,रश्मि सोनी,चंचला शांडिल्य,हामिदा बानो सहित महिला कांग्रेस की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

स्वतंत्रता दिवस से पहले 8 आजीवन कारावास के कैदी रिहा

अच्छे आचरण का मिला लाभ,जेल में काम के आधार पर अनुभव प्रमाण-पत्र और पारिश्रमिक भी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

स्वतंत्रता दिवस से पहले सेंट्रल जेल अंबिकापुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आठ कैदियों को शासन के नियमों के तहत समय पूर्व रिहा किया गया। जेल में अच्छे आचरण और व्यवहार के आधार पर इन कैदियों की रिहाई की गई है। वहीं 14 अगस्त को आठ और कैदियों को रिहा किया जाएगा। सेंट्रल जेल में वर्तमान में हत्या,दुष्कर्म,चोरी,लूट,डकैती सहित अन्य अपराधों के 2,181 बंदी और कैदी निरुद्ध हैं। जेल अधीक्षक अक्षय सिंह राजपूत ने बताया कि नियम 358 के तहत जेल अधीक्षक,पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद दंडादेश बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर समय पूर्व रिहाई की कार्रवाई की जाती है। इस प्रक्रिया के तहत आठ आजीवन कारावास के कैदियों को रिहा किया गया है। उन्होंने बताया कि रिहा किए गए कैदियों ने जेल में रहते हुए विभिन्न शाखाओं में काम किया। उनके कार्य के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र और पारिश्रमिक भी प्रदान किया गया है। जेल अधीक्षक ने कहा कि कैदियों की रिहाई का पल उनके साथ जेल प्रशासन के लिए भी भावुक होता है। लंबे समय तक जेल में रहने के दौरान कैदी विभिन्न शाखाओं में काम करते हैं और जेल की व्यवस्थाओं में सहयोग करते हैं। अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई मिलने से उन्हें शेष जीवन परिवार के साथ बेहतर तरीके से बिताने का अवसर मिलता है।

15 साल बाद घर लौटे ओमप्रकाश

हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सीतापुर के ग्राम कोटछाल निवासी ओमप्रकाश धनकी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रिहा होने की खुशी है। करीब 15 वर्ष पूर्व जाने-अनजाने में हुई गलती का उसे पछतावा है। मृतक की आत्मा की शांति की कामना करते हुए वह भावुक हो गया। उसने कहा कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करने का प्रयास रहेगा और परिवार के साथ शेष जीवन बिताएगा। कोटछाल निवासी मुकेश धनकी ने बताया कि हत्या के मामले में करीब 15 साल की सजा काटने के बाद अब घर लौट रहा है। उसने कहा कि शासन की योजना का लाभ मिलने से वह खुश है। पूर्व में सरपंच रह चुके मुकेश ने कहा कि अब परिवार के साथ खेती-बाड़ी कर शेष जीवन शांतिपूर्वक बिताएगा।

पद्मिनी कोल्हापुरी के हाथों डॉ. डीके सोनी को मिला 'प्राइड ऑफ भारत अवार्ड 2026'

जनहित,सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मिला राष्ट्रीय सम्मान,यह डॉ. सोनी का 52वां अवार्ड

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

जनहित,सामाजिक न्याय,पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों के लिए लंबे समय से सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता,अधिवक्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ.डीके सोनी को प्रतिष्ठित 'प्राइड ऑफ भारत अवार्ड 2026' से सम्मानित किया गया। मुंबई के होटल हॉलिडे इन में 8 अगस्त 2026 को आयोजित भव्य समारोह में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी के करकमलों से डॉ. सोनी को सम्मान पत्र एवं अवार्ड प्रदान किया गया। डॉ.सोनी के लिए यह सम्मान इसलिए भी खास रहा,क्योंकि यह उनके सामाजिक और कानूनी क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को मिली राष्ट्रीय पहचान के साथ-साथ उनका 52वां अवार्ड है। सम्मान समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से डॉक्टर,सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियां शामिल हुईं।

आरटीआई और जनहित याचिकाओं के जरिए उठाते रहे हैं जनहित के मुद्दे : डॉ. डीके सोनी लंबे समय से आम नागरिकों के अधिकारों,

सामाजिक न्याय और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के लिए सक्रिय हैं। उन्होंने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई को आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए कई मामलों में जानकारी सामने लाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न जनहित से जुड़े मामलों को जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालयों तक पहुंचाया। उनका कहना है कि जब किसी मामले में आम नागरिक की आवाज प्रशासनिक स्तर पर नहीं सुनी जाती,तब कानूनी माध्यमों का सहारा लेकर उसे उचित मंच तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है।

भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों को भी उठाया : सरकारी विभागों में कथित भ्रष्टाचार,अनियमितताओं और लापरवाही से जुड़े मामलों को सामने लाने में भी डॉ.सोनी लगातार सक्रिय रहे हैं। उनके द्वारा विभिन्न मामलों में दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर संबंधित विभागों एवं अधिकारियों के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत की गई तथा आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। कई मामलों को उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाया। उनका जोर इस बात पर रहा है कि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता हो और सार्वजनिक धन एवं सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नियमानुसार हो।

'सरगुजा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस' के माध्यम से प्रयास : डॉ. सोनी अपनी संस्था 'सरगुजा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस' के माध्यम से भी सामाजिक न्याय और आम नागरिकों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। संस्था के माध्यम से जरूरतमंद और वंचित लोगों को न्याय दिलाने तथा उनकी समस्याओं को संबंधित मंच तक पहुंचाने के प्रयास किए जाते हैं। उनके कार्यक्षेत्र में आरटीआई,सामाजिक न्याय,जनहित के मुद्दे,सुशासन,नागरिक अधिकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना प्रमुख रूप से शामिल रहा है।

मुंबई में जुटीं देशभर की हस्तियां : 'प्राइड ऑफ भारत अवार्ड 2026' का आयोजन मुंबई के होटल हॉलिडे इन में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मनीश बंसल,फाउंडर इनसाइटसक्सेस एंड ट्रेड मीडिया द्वारा किया गया था। समारोह में देश के अलग-अलग राज्यों से आए विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों की मौजूदगी रही। इसी मंच पर डॉ. डीके सोनी को उनके सामाजिक एवं जनहितकारी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी के हाथों सम्मान प्राप्त करना उनके लिए विशेष उपलब्धि रहा।

52वां अवार्ड मिलने पर बोले...

जिम्मेदारी और बढ़ी : सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉ. डीके सोनी ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए केवल पुरस्कार नहीं, बल्कि जनहित और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करने की जिम्मेदारी को और बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी आम नागरिकों, वंचितों और जरूरतमंद लोगों के अधिकारों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आरटीआई और कानूनी माध्यमों के जरिए व्यवस्था में पारदर्शिता लाने तथा लोगों को उनका अधिकार दिलाने का प्रयास आगे भी जारी रहेगा।

सरगुजा के लिए भी गौरव का विषय

डॉ. डीके सोनी को राष्ट्रीय स्तर पर मिले इस सम्मान की खबर के बाद अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं और उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी। लोगों ने कहा कि जनहित और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सरगुजा से लगातार सक्रिय रहने वाले डॉ. सोनी को मिला यह सम्मान पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। राष्ट्रीय मंच पर मिला यह 52वां सम्मान डॉ. डीके सोनी की वर्षों से जारी सामाजिक एवं कानूनी सक्रियता को एक और पहचान देने वाला साबित हुआ है।

भव्य तिरंगा यात्रा के साथ 2.42 करोड़ रू के विद्युत सब-स्टेशन का लोकार्पण और महतारी सदन का भूमिपूजन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

स्वतंत्रता दिवस के पूर्व अंबिकापुर के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम केदमा में राष्ट्रभक्ति, विकास और महिला सशक्तिकरण का अनूठा संगम देखने को मिला। ग्राम केदमा में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं अंबिकापुर विधायक श्री राजेश अग्रवाल शामिल हुए। इस अवसर पर ग्रामवासियों को विकास की दो महत्वपूर्ण सौगातें मिलीं। मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने 2 करोड़ 42 लाख की लागत से निर्मित विद्युत सब-स्टेशन का लोकार्पण किया तथा महतारी सदन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।

एक ओर हाथों में तिरंगा लेकर निकली यात्रा ने पूरे क्षेत्र को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों की सौगात ने ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर बुनियादी सुविधाओं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई उम्मीद जगाई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों, महिलाओं,युवाओं,जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की सहभागिता से कार्यक्रम उत्साह और उमंग से भर उठा।

तिरंगे के साथ गूंजे भारत माता के जयकारे

ग्राम केदमा में निकली तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम् और जय हिंद के नारों से वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। युवाओं के साथ महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी ने यात्रा को भव्य स्वरूप प्रदान किया। तिरंगा यात्रा के दौरान राष्ट्रीय एकता,अखंडता,भाईचारे और राष्ट्र प्रेम का संदेश जन-जन तक पहुंचा। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व आयोजित इस यात्रा ने क्षेत्र में देशभक्ति की भावना को और प्रबल किया।

पानी के लिए खोदे गड्ढे में डूबा 2 साल का मासूम,मौत

-संवाददाता-
बतौली,13 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बांसाझाल में पानी के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,2 वर्षीय निलेश अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान खेलते-खेलते वह पानी के लिए खोदे गए गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे में पानी भरा होने के कारण वह डूब गया और दम घुटने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। मासूम की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर बतौली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।

सुपरमैन की एक और दबिश...किराए के मकान में चल रही थी 'महुआ शराब फैक्ट्री'

8 भट्ठियां एक साथ चढ़ी मिलीं,480 किलो महुआ लाहन और 70 लीटर शराब जब्त,इंजेक्शन से लेकर एमपी की शराब तक लगातार कार्रवाई, फिर भी बड़े नेटवर्क पर सवाल बरकरार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले अंबिकापुर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता ने पटपरिया स्थित संकटमोचन मंदिर के पास एक किराए के मकान में दबिश देकर कथित रूप से चल रही महुआ शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से 8 चढ़ी हुई भट्ठियां, 70 लीटर महुआ शराब और 480 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया। मामले में अर्जुन कुजुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में हुई। मुखबिर की सूचना पर टीम किराए के मकान तक पहुंची तो एक कमरे में आठ भट्ठियों पर शराब बनाने का काम चल रहा था, जबकि दूसरे कमरे में 24 प्लास्टिक डिब्बों में महुआ लाहन रखा मिला। टीम ने शराब जब्त की और लाहन मौके पर नष्ट कराया। शराब बनाने के उपकरण और बर्तन भी जब्त किए गए। विभाग के अनुसार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)(च), 34(2) और 59(क) के तहत कार्रवाई की गई है।

व्यंग्य में कहें तो 'विलेन' बदल रहे हैं, फिल्म वही है : हर कार्रवाई के बाद एक नया आरोपी सामने आता है। एक आरोपी जेल जाता है, पूछताछ में दूसरे का नाम आता है और फिर अगली दबिश में दूसरा आरोपी भी जेल पहुंच जाता है। यह कार्रवाई की सफलता है या नेटवर्क की गहराई का संकेत–यह जांच का विषय है।

क्योंकि अगर एक किराए के मकान में एक साथ आठ भट्ठियां चल रही थीं,तो सवाल केवल अर्जुन कुजुर तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि कच्चा माल कहां से आया,तैयार शराब की बिक्री कहां होती थी,ग्राहक कौन थे और इस कथित कारोबार से जुड़े अन्य लोग कौन हैं।

सुपरमैन की 'स्पीड' फिर चर्चा में...

सुपरमैन रंजीत गुप्ता की अगुवाई वाला उड़नदस्ता पिछले कुछ समय से लगातार कार्रवाई कर रहा है। कभी नशीले इंजेक्शन की खेप, कभी कथित सप्लायर, कभी हजारों कैप्सूल और अब एक ही मकान में आठ भट्ठियां–कार्रवाइयों की फेहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। यही वजह है कि विभागीय हलकों में रंजीत गुप्ता को मजाकिया अंदाज में 'सुपरमैन' कहने की चर्चा भी तेज है। मुखबिर से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचना, बरामदगी करना और आरोपियों को जेल भेजना–कार्रवाई की यह गति निश्चित रूप से ध्यान खींचती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है।

इंजेक्शन से शराब तक...हर बार एक नई कड़ी

पिछली कार्रवाइयों को जोड़कर देखें तो ऑपरेशन क्लीन की कहानी केवल आज की आठ भट्ठियों तक सीमित नहीं है। वाहिद अंसारी की गिरफ्तारी के बाद मोशीम अंसारी तक कार्रवाई पहुंची। साहिल तिर्की के बाद नितीश गुप्ता गिरफ्तार हुआ। सीतापुर में सजाद अली के बाद महबूब खान तक टीम पहुंची। ब्रह्मपारा में आशा पांडेय के बाद राजेश मंदिलवार उर्फ बुटन गिरफ्तार हुआ। इसके बाद अंबिकापुर के अविनाश पैकरा से पूछताछ के आधार पर बलरामपुर के अमर विश्वकर्मा उर्फ बिट्टू तक टीम पहुंची। वहीं गंगापुर में विजय गिरी के घर से 200 किलो महुआ लाहन और 15 लीटर महुआ शराब बरामद हुई थी। कुछ दिन पहले नुनेरा गांव में 18 पेटियों में 900 पाव यानी 162 लीटर मध्यप्रदेश की गोवा व्हिस्की बरामद कर दो आरोपियों को जेल भेजा गया। और अब पटपरिया में आठ भट्ठियों से 70 लीटर शराब और 480 किलो लाहन।

'90 प्रतिशत विक्रेता जेल में' दावे के बाद भी नए मामले : नशीले इंजेक्शन के मामले में विभाग पहले ही दावा कर चुका है कि अंबिकापुर के लगभग 90 प्रतिशत विक्रेता जेल भेजे जा चुके हैं। इसके बावजूद बाद में बलरामपुर से कथित सप्लायर पकड़ में आया। इसी तरह अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई के बावजूद शहर और आसपास के इलाकों से महुआ शराब की भट्ठियां और बड़ी मात्रा में लाहन बरामद होना बताता है कि समस्या केवल एक-दो आरोपियों की नहीं हो सकती। यही वह बिंदु है जहां 'सुपरमैन' की असली परीक्षा शुरू होती है।

अब सवाल गिरफ्तारी से आगे का है...

लगातार कार्रवाई से आबकारी विभाग की सक्रियता जरूर सामने आ रही है। लेकिन कार्रवाई की अगली मंजिल केवल गिरफ्तारी और जब्ती तक सीमित न रहकर पूरे नेटवर्क तक पहुंचना जरूरी है।

- कौन कच्चा माल उपलब्ध कराता है?
- कौन शराब की बिक्री करवाता है?
- कौन परिवहन करता है?
- कहां-कहां इसकी सप्लाई होती है?
- और क्या इन मामलों के पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क भी है?

इन सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं। फिलहाल सुपरमैन रंजीत गुप्ता की टीम की एक और बड़ी कार्रवाई की चर्चा है। आठ भट्ठियां बंद हुई हैं, 480 किलो लाहन नष्ट हुआ है और 70 लीटर शराब जब्त हुई है। लेकिन अगर ऑपरेशन क्लीन को वास्तव में सफल बनाना है तो अगली सुर्खी केवल 'एक और आरोपी गिरफ्तार' की नहीं, बल्कि 'अवैध शराब के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश' की होनी चाहिए। कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक टीआर केहरी,मुख्य आरक्षक अशोक सोनी, नगर सैनिक रणविजय सिंह,रोहित सोनी तथा आबकारी स्टाफ नीरज चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

स्वतंत्रता दिवस का फाइनल रिहर्सल : पीजी कॉलेज मैदान में दिखा देशभक्ति का जोश,13 प्लाटूनों ने किया मार्चपास्ट

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। बुधवार को पीजी कॉलेज ग्राउंड में 15 अगस्त को होने वाले जिला स्तरीय मुख्य समारोह का फाइनल रिहर्सल हुआ। अपर कलेक्टर सुनील नायक ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाते हुए ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। कलेक्टर अजीत वसंत और एसएसपी राजेश अग्रवाल ने समारोह स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फाइनल रिहर्सल में पुलिस,नगर सैनिक बल,नव आरक्षक दल, एनसीसी,स्काउट और गाइड्स सहित कुल 13 प्लाटूनों ने अनुशासित मार्चपास्ट किया। परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत और सेकंड इन परेड कमांडर प्रशिक्षु पेविन वर्मा के नेतृत्व में दलों ने शानदार प्रदर्शन किया।

पुलिस बैंड से लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहेंगी आकर्षण : 15 अगस्त को मुख्य समारोह में पुलिस बैंड की प्रस्तुति के साथ पुलिस जवानों और स्कूली विद्यार्थियों की पीटी परेड होगी। नवोदय, कार्मेल स्कूल, होलीक्रॉस, मोंटफोर्ट, उर्सू लाइन और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी देशभक्ति गीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियां देंगे। समारोह में शहीद जवानों के परिवारों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।

मंत्री रामविचार नेताम करेंगे ध्वजारोहण : जिला स्तरीय मुख्य समारोह 15 अगस्त को पीजी कॉलेज ग्राउंड, अम्बिकापुर में होगा। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास तथा कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण करेंगे।

व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश : कलेक्टर अजीत वसंत ने बैठक व्यवस्था,साउंड सिस्टम,बेरिकेटिंग, पेयजल और विद्युत व्यवस्था सहित सभी तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को समारोह स्थल की सभी व्यवस्थाएं समय से दुरुस्त करने और कार्यक्रम को गरिमामय एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त डीएन कश्यप, एसडीएम बनसिंह नेताम, आदिवासी सहायक आयुक्त ललित शुक्ला सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

500 साल पुरानी लोकआस्था को मिलेगा भव्य स्वरूप,नाथल दाई मंदिर निर्माण का भूमि पूजन

आठ-दस ग्राम पंचायतों से पहुंचे श्रद्धालु....महाआरती, हनुमान चालीसा पाठ और महाभंडारे में उमड़ा जनसैलाब

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

ग्राम बेनीपुर स्थित करीब 500 वर्ष से अधिक पुरानी लोकआस्था से जुड़े नाथल दाई धाम को अब भव्य मंदिर का स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। गुरुवार को मंदिर निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन किया गया। धार्मिक अनुष्ठान में आसपास की आठ-दस ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु पहुंचे। महाआरती, हनुमान चालीसा पाठ और महाभंडारे के दौरान पूरा परिसर भक्तिमय नजर आया।

छह बैगाओं ने पारंपरिक विधि से कराई पूजा : कार्यक्रम की शुरुआत सुबह करीब 7 बजे छह बैगाओं द्वारा पारंपरिक विधि-विधान से पूजा-अर्चना के साथ हुई। ग्रामीण अपने-अपने घरों से अक्षत और पुष्प लेकर पहुंचे और माता नाथल दाई को अर्पित किए। बैगाओं ने काफी देर तक पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ पूजा संपन्न कराई। पूजा के बाद माता नाथल दाई की महाआरती और हनुमान चालीसा पाठ किया गया। इसके बाद मां महामाया की आरती भी हुई। महाआरती में भारत सिंह सिसोदिया,अनुराग सिंह देव, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह और मेजर अनिल सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

पांच फावड़े चलाकर शुरू किया मंदिर निर्माण : महाआरती के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह ने मंदिर निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन किया। उन्होंने पांच फावड़े चलाकर निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस दौरान नाथल दाई सेवा समिति के सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं ने प्राचीन स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। आसपास की आठ-दस ग्राम पंचायतों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी मंदिर निर्माण के संकल्प में सहभागिता की। कार्यक्रम के बाद आयोजित महाभंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

लोकगीतों और पीढ़ियों की स्मृतियों में सुरक्षित है इतिहास : हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक आलोक सिंह ने कहा कि सरगुजा की लोक संस्कृति में देवी-देवताओं से जुड़े अनेक स्थल ऐसे हैं, जिनका इतिहास केवल शिलालेखों में नहीं,बल्कि लोकगीतों, बुजुर्गों की स्मृतियों और पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों और बुजुर्गों की मान्यता के अनुसार नाथल दाई का यह स्थल करीब 500 वर्ष से अधिक पुराना है। यहां माता नाथल दाई को चंद्रहासिनी देवी की बहन तथा मां कामाख्या की छोटी बहन के रूप में पूजित माना जाता है। सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में बैगा,गुनिया और देवार समुदाय द्वारा पारंपरिक पूजा-पाठ के दौरान मां महामाया और चंद्रहासिनी देवी के साथ नाथल दाई का भी आह्वान किए जाने की परंपरा बताई जाती है।

भव्य मंदिर बनाने का संकल्प : नाथल दाई सेवा समिति ने इस प्राचीन लोकआस्था के केंद्र को भव्य मंदिर के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। भूमि पूजन समारोह में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने मंदिर निर्माण के प्रति क्षेत्रवासियों की आस्था और सहभागिता को भी सामने रखा। कार्यक्रम में अनुज दुबे, जनमेजय मिश्रा, निलेश सिंह, रूपेश दुबे, सेवा समिति अध्यक्ष अर्जुन पटेल,उपाध्यक्ष सतीश यादव, सचिव एवं सरपंच हरिशंकर सहित ननका बैगा,पंडा ललन प्रसाद,चंदर यादव,सुखलाल राजवाड़े, राजू यादव,भदर यादव,धनसी,राम आशीष, डिलेश्वर पैकरा,ललित रजवाड़े, नंदकेश्वर रजवाड़े, बुधन राम पैकरा, बरन राम, ननका यादव, कुमार राम, जितेंद्र सिंह, कन्हैया लाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं श्रद्धालु मौजूद रहे।

मुख्य द्वार पर विशाल ध्वज, चारों कोनों पर भी ध्वज

धार्मिक आयोजन के समापन पर मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर एक विशाल ध्वज स्थापित किया गया। इसके अलावा परिसर के चारों कोनों पर भी ध्वज लगाए गए। ध्वज स्थापना के बाद पूरा मंदिर परिसर धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर हो उठा।

प्राचीन मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद

विश्व हिंदू परिषद सरगुजा के जिलाध्यक्ष विनीत गुप्ता ने बताया कि ग्राम बेनीपुर में माता नाथल देवी के प्राचीन मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद हैं और स्थल पर बाउंड्रीवॉल भी निर्मित है। उनके अनुसार प्राचीन समय से ही बैगा, गुनिया, देवार और ग्रामीण समुदाय यहां पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण परंपराओं में होने वाले विभिन्न पूजा-पाठ में माता नाथल देवी की भी आराधना की जाती रही है। लोक मान्यता के अनुसार उन्हें माता कामाख्या के लघु स्वरूप के रूप में भी पूजा जाता है।

सड़क पर मवेशी,खेतों में फसल की बर्बादी परेशान ग्रामीण कलेक्टोरेट ले पहुंचे गाय-बैल

13 किमी दूर से मवेशियों को हांककर लाए ग्रामीण, बोले-सड़क पर हादसे और खेतों में नुकसान से दोहरी मार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

निराश्रित मवेशियों से परेशान ग्राम परसा-भकुरा के ग्रामीणों ने गुरुवार को अनोखे अंदाज में प्रशासन का ध्यान समस्या की ओर खींचा। अंबिकापुर-रामानुजगंज नेशनल हाइवे पर घूम रहे गाय-बैलों को ग्रामीण करीब 13 किलोमीटर दूर कलेक्टोरेट तक हांककर ले आए। इसके बाद सभी मवेशियों को कलेक्टोरेट परिसर में छोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बैठे मवेशियों से लगातार हादसे का खतरा बना हुआ है, वहीं खेतों में घुसकर ये फसल भी बर्बाद कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार परसा-भकुरा क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क पर बड़ी संख्या में निराश्रित गाय-बैल दिनभर बैठे रहते हैं। रात के समय सड़क पर बैठे मवेशी वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। कई बार बाइक, कार और भारी वाहनों के चालक इनसे टकराकर हादसे का शिकार हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या केवल सड़क तक सीमित नहीं है। निराश्रित मवेशी खेतों में पहुंचकर धान, मक्का समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शहर में पकड़े जाने वाले कुछ मवेशियों को रात के समय गांव की ओर छोड़ दिया जाता है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। समस्या से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर घूम रहे मवेशियों को एकत्र किया और उन्हें हांकते हुए कलेक्टोरेट पहुंच गए। परिसर में बड़ी संख्या में गाय-बैल पहुंचने से वहां मौजूद अधिकारी-कर्मचारी भी हैरान रह गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि मवेशियों को रखने के लिए उचित व्यवस्था की जाए, जहां उनके चारे और रहने का इंतजाम हो। ग्राम पंचायत परसा के पूर्व सरपंच ने कहा कि सड़क पर मवेशियों के बैठे रहने से लगातार दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। प्रशासन को मवेशियों के साथ-साथ उन्हें खुला छोड़ने वाले पालकों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

मवेशी तस्करी का आरोपी झारखंड के गुमला से गिरफ्तार....

बतौली पुलिस की कार्रवाई : 13 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जा रहा था पिकअप, खराब हुआ चक्का तो वाहन छोड़कर भागे थे तस्कर

-संवाददाता-
अंबिकापुर/बतौली,13 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

मवेशी तस्करी के मामले में बतौली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए झारखंड के गुमला निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल किए गए पिकअप वाहन से संबंधित साक्ष्य भी जुटाए हैं। मामले में 13 मवेशियों को क्रूरतापूर्वक पिकअप में ठूंस-ठूंसकर झारखंड के बूचड़खाने ले जाने का आरोप है। प्रकरण में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

पिकअप का चक्का खराब हुआ तो मवेशियों को छोड़कर भागे

पुलिस के अनुसार 17 जनवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पिकअप क्रमांक JH-01-FY-8400 में 6 गाय और 7 बछिया समेत कुल 13 मवेशियों को सींग और पैर बांधकर क्रूरता एवं निर्दयतापूर्वक ठूंस-ठूंसकर छत्तीसगढ़ से झारखंड ले जाया जा रहा है। सूचना पर बतौली पुलिस ने ग्राम बोदा बगीचा रोड स्थित घोषरा पखना खेत के पास पहुंचकर कार्रवाई की। इसी दौरान पिकअप के पिछले चक्के का नट-बोल्ट टूट गया था। वाहन खराब होने के बाद चालक और अन्य तस्कर पिकअप तथा मवेशियों को मौके पर छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने मौके से पिकअप वाहन और 13 मवेशियों को बरामद कर जब्त किया तथा मामले में वाहन चालक और अन्य मवेशी तस्करों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की।

वाहन के नंबर से पहुंची पुलिस झारखंड : मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पिकअप के पंजीयन नंबर के आधार पर वाहन मालिक और उससे जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस टीम को झारखंड भेजा गया। टीम ने गुमला पहुंचकर वाहन स्वामी एवं अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की। जांच में पुलिस को पिकअप वाहन के माध्यम से मवेशियों की तस्करी किए जाने से संबंधित जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने अयान अहमद पिता मोहम्मद अशगर, उम्र 21 वर्ष, निवासी गुमला, झारखंड को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

मोबाइल में मिला तस्करी का वीडियो : पुलिस के अनुसार आरोपी के मोबाइल फोन की जांच के दौरान पिकअप वाहन में मवेशियों को ले जाने से संबंधित वीडियो भी मिला। पुलिस ने आरोपी को विवेचना में सहयोग करने के लिए धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी किया था,लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। विवेचना में आरोपी की संलिप्तता पाए जाने के बाद उसके विरुद्ध धारा 3(5) बीएनएस भी जोड़ी गई। दूसरे राज्य का निवासी होने और आवश्यकता पड़ने पर जांच में उपस्थित होने में असमर्थ रहने की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई है।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी : पुलिस के अनुसार मामले में अन्य आरोपी अभी फरार हैं। उनकी पतासाजी और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रकरण में आगे की विवेचना एवं वैधानिक कार्रवाई जारी है।

बरामदगी : 13 मवेशी, मवेशी तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक JH-01-FY-8400 पूरी कार्रवाई में थाना बतौली प्रभारी निरीक्षक विवेक सेंगर, सहायक उप निरीक्षक अरुण गुप्ता, आरक्षक राकेश एक्का एवं आरक्षक विकास एक्का सक्रिय रहे।

हवाला के जरिए एक करोड़ से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप एसआई और आरक्षक लाइन अटैच

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

अंबिकापुर के सीएसपी समेत तीन पुलिस अधिकारियों पर हवाला के माध्यम से एक करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत लेने के आरोपों के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने प्रथम दृष्टया संज्ञान लिया है। अदालत ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी, सीबीआई निदेशक और संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। इधर,मामला सामने आने के बाद आईजी दीपक झा ने साइबर थाने में पदस्थ एसआई और आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है।

शिकायत पर कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट : विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/ सीबीआई-11 सुधांशु कौशिक की अदालत में 1 जुलाई 2026 को आकाश कुमार की ओर से बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत शिकायत पेश की गई थी। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनमीत सिंह ने पक्ष रखा। शिकायत के साथ शपथ-पत्र भी संलग्न किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अंबिकापुर में पदस्थ आईपीएस राहुल बंसल ने साइबर थाना सरगुजा में पदस्थ एएसआई और आरक्षक के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा। आरोप है कि इसके तहत हवाला चैनल के माध्यम से एक करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत की मांग की गई और रकम स्वीकार भी की गई। शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 व 7ए तथा बीएनएस की धारा 308 व 351 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

वायरल ऑडियो की भी जांच : मामले में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें हवाला के जरिए रिश्वत के लेन-देन की बातचीत होने का दावा किया गया है। ऑडियो में आईपीएस राहुल बंसल का नाम आने की बात कही जा रही है। पुलिस अब ऑडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता और बातचीत में शामिल बताए जा रहे लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

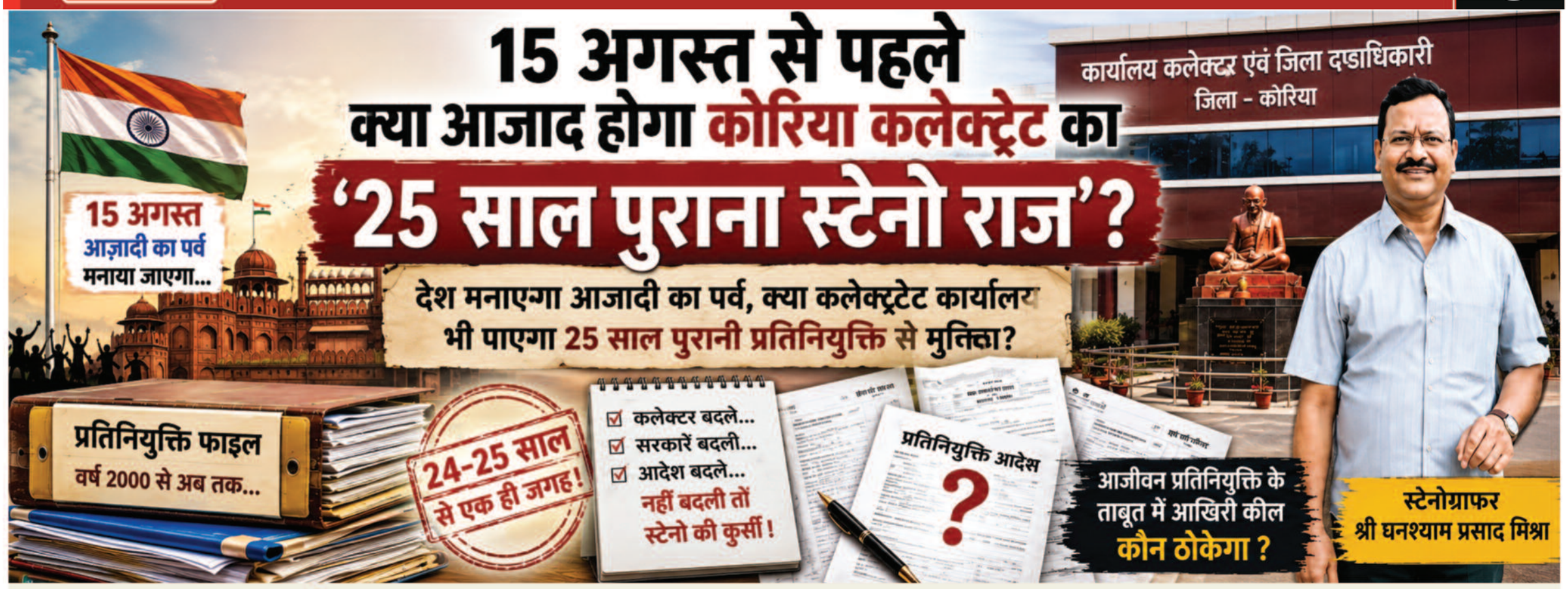

15 अगस्त पर देश आजाद, लेकिन कोरिया कलेक्टरेट में 25 साल पुरानी प्रतिनियुक्ति कब होगा आजाद?

आजादी का पर्व करीब, कोरिया कलेक्टरेट में 25 साल पुरानी 'गुलामी' कब खत्म होगी?

कलेक्टर बदले, सरकारें बदलीं, आदेश बदले...नहीं बदली तो 25 साल पुरानी स्टेनो की कुर्सी!

15 अगस्त से पहले प्रशासन के लिए आखिरी परीक्षा—क्या 25 साल पुरानी प्रतिनियुक्ति होगी समाप्त?

25 साल से एक ही कुर्सी पर 'स्थायी मेहमान', क्या 15 अगस्त से पहले होगी मूल विभाग में वापसी?

3 साल में डेरक बदलने का शासनादेश के बाद क्या कोरिया में 25 साल पुरानी कुर्सी बदलेगी?

कमिश्नर का अनोखा पदस्थापना आदेश...कोरिया में पदस्थ स्टेनोग्राफर का काम एमसीबी में, वेतन कोरिया से, वर्षों से जमे स्टेनो टू कलेक्टर पर अब शासन की नई व्यवस्था की अग्निपरीक्षा

एक पद, तीन जिले और 25 साल पुराना सवाल-आखिर कोरिया में चल क्या रहा है?

जशपुर के स्टेनोग्राफर को कोरिया में पदस्थापना, काम एमसीबी में, कोरिया के पदोन्नत स्टेनोग्राफर को भी नई जिम्मेदारी—पुरानी व्यवस्था पर कब लगेगी निर्णायक समीक्षा?

मत्स्य विभाग से जुड़े घनश्याम मिश्रा के वर्षों पुराने संलग्नीकरण/प्रतिनियुक्ति प्रकरण के बीच 3 अगस्त का नया शासन आदेश भी महत्वपूर्ण

-रवि सिंह-

बैकुण्ठपुर, 13 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

देश 15 अगस्त को आजादी का पर्व मनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कोरिया कलेक्टरेट में करीब 25 वर्षों से जारी एक प्रतिनियुक्ति को लेकर सवाल अब भी जस के तस खड़े हैं, एक ओर शासन-प्रशासन तबादले, पदस्थापना और लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों को हटाने की व्यवस्था की बात करता है, वहीं दूसरी ओर कलेक्टर कार्यालय के स्टेनो पद पर वर्षों से जमे मत्स्य विभाग से जुड़े कर्मचारी की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं बदली—यह सवाल लगातार उठ रहा है, ऐसे में जिले में चर्चा है कि क्या 15 अगस्त से पहले कलेक्टर कार्यालय इस कथित 'आजीवन प्रतिनियुक्ति' से आजाद हो पाएगा, या फिर 25 साल पुरानी यह व्यवस्था एक और साल अपनी 'आजादी' मनाएगी? क्योंकि सरकारी फाइलों में शब्द बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कई बार उन शब्दों के बीच छिपी व्यवस्था उससे भी ज्यादा सवाल खड़े कर देती है, कोरिया कलेक्टर कार्यालय में लंबे समय से स्टेनो टू कलेक्टर के रूप में कार्यरत घनश्याम मिश्रा को लेकर दैनिक घटती-घटना द्वारा लगातार दस्तावेजों के आधार पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, अब सरगुजा संभाग आयुक्त कार्यालय से जारी एक नया पदोन्नति एवं पदस्थापना आदेश सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

एक आदेश में कोरिया, एमसीबी और जशपुर...प्रशासनिक नक्शे पर स्टेनोग्राफर की नई कहानी-11 जून 2026 को आयुक्त, सरगुजा संभाग कार्यालय, अंबिकापुर से जारी आदेश में राजस्व विभाग के अंतर्गत संभागीय कार्यालयों और जिलों में पदस्थ स्टेनोग्राफर वर्ग-3 को स्टेनोग्राफर वर्ग-2 के पद पर पदोन्नत करते हुए पदस्थापना की गई है, इसी आदेश में संजय कुमार कुशवाहा को कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरिया में पदस्थ किया गया, लेकिन आदेश की शर्त में उन्हें उपस्थिति देने के तत्काल बाद आगामी आदेश तक कार्यालय कलेक्टर, जिला एमसीबी में कार्य करने की व्यवस्था दी गई है, उनके वेतन-भत्तों का भुगतान पदस्थी कार्यालय से किए जाने की बात भी आदेश में दर्ज है, दूसरी ओर सुरेश कुमार यादव को स्टेनोग्राफर वर्ग-2 के पद पर पदोन्नत कर कार्यालय कलेक्टर, जिला जशपुर में पदस्थ किया गया है, यहीं से सवाल उठता है—यदि कोरिया में स्टेनोग्राफर की आवश्यकता थी तो पदस्थ कर्मचारी को उसी कार्यालय में काम क्यों नहीं कराया गया? और यदि एमसीबी में आवश्यकता थी तो कोरिया में पदस्थापना का ढांचा क्यों बनाया गया? यह प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर लिया गया निर्णय हो सकता है, लेकिन आदेश की इस असामान्य दिखाई देने वाली व्यवस्था का कारण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना अब जरूरी हो गया है, यदि इसमें कोई विसंगति है तो वर्षों से उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दैनिक घटती-घटना इस विषय पर लगातार समाचार प्रकाशित करता रहा है, अब तक इस प्रकरण से जुड़े 14 समाचार और दस्तावेजी खुलासे सामने रखे जा चुके हैं, प्रतिनियुक्ति से जुड़े पुराने आदेशों से लेकर सेवा पुस्तिका, वेतन, संविलियन के प्रयास, पदस्थापना और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब में अभी तक वैसी स्पष्ट प्रशासनिक कार्रवाई दिखाई नहीं देती, जिसकी अपेक्षा इतने लंबे समय से उठ रहे सवालों के बाद की जाती है।

घनश्याम मिश्रा के लिए रास्ता खुला या महज संयोग?-यही वह बिंदु है जहां इस खबर का सबसे तीखा सवाल पैदा होता है, यदि कोरिया कलेक्टर कार्यालय में नए स्टेनोग्राफर की पदस्थापना की गई है, लेकिन उसे एमसीबी में कार्य करने की व्यवस्था दी गई है, तो स्वाभाविक रूप से यह जानना जरूरी है कि कोरिया कलेक्टर कार्यालय में स्टेनोग्राफर का वास्तविक कार्य कौन करेगा? क्या वहां पहले से कार्यरत कर्मचारी ही वही भूमिका निभाता रहेगा? यदि हां, तो उसके लिए वर्तमान प्रशासनिक आधार क्या है? क्या उसकी प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण वैध रूप से अभी प्रभावी है? क्या सक्षम विभाग ने उसकी अवधि बढ़ाई है? क्या मूल विभाग ने उसकी वापसी के संबंध में कोई निर्णय लिया है? इन प्रश्नों का उत्तर आदेशों और सेवा रिकॉर्ड से दिया जा सकता है, यह कहना कि नया आदेश जानबूझकर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है ये कहना गलत नहीं होगा।

'अपने कर्मचारी' बनाम 'दूसरे विभाग के कर्मचारी' का सवाल-घनश्याम मिश्रा को लेकर उठ रहा सबसे संवेदनशील सवाल यही है कि यदि वे मूलतः किसी अन्य विभाग से संबंधित हैं, तो राजस्व प्रशासन में उनकी इतनी लंबी भूमिका का प्रशासनिक आधार क्या है? यहां किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उद्देश्य नहीं है, मुद्दा यह है कि सरकारी व्यवस्था व्यक्ति से बड़ी होती है, यदि किसी कर्मचारी को दूसरे विभाग में लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए नियम होना चाहिए, यदि नियम है तो आदेश होना चाहिए, यदि आदेश है तो अवधि होनी चाहिए, यदि अवधि समाप्त होती है तो समीक्षा होनी चाहिए, और यदि विशेष परिस्थिति में व्यवस्था जारी रखनी है तो उसका कारण दर्ज होना चाहिए।

कलेक्टर बदलते गए, लेकिन स्टेनो की कुर्सी नहीं बदली!

कोरिया जिले के सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि समय-समय पर जिले में कलेक्टर बदलते रहे हैं, जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विभिन्न समय में पदस्थ रहे कलेक्टरों की सूची उपलब्ध है, यानी कुर्सी बदलती रही, चेहरे बदलते रहे, सरकारें बदलीं, प्रशासनिक प्राथमिकताएं बदलीं, लेकिन इस प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ही कर्मचारी की कलेक्टर कार्यालय में मौजूदगी इतनी लंबी कैसे बनी रही? व्यंग्य तो अब यही किया जा रहा है कि कलेक्टर का तबादला सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन स्टेनो की कुर्सी शायद प्राकृतिक धरोहर है, यह व्यंग्य कोई सरकारी तथ्य नहीं है, बल्कि लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच पैदा हुई सार्वजनिक चर्चा को दर्शाता है, और यही चर्चा प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

आजीवन प्रतिनियुक्ति के ताबूत में आखिरी कील कौन ठोकेगा?

और अब इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा सवाल फिर वहीं पहुंचता है जहां से यह कहानी शुरू हुई थी, क्या यह वर्षों पुरानी प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण व्यवस्था कभी समाप्त होगी? क्या संबंधित कर्मचारी को उसके मूल विभाग में वापस भेजा जाएगा? क्या शासन इस पूरे मामले की स्वतंत्र समीक्षा कराएगा? क्या सेवा पुस्तिका, प्रतिनियुक्ति आदेश, वेतन निर्धारण, पदोन्नति और सेवा निरंतरता की पूरी श्रृंखला की जांच होगी? या फिर यह व्यवस्था सरकारी फाइलों में इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब उसे बदलना ही सबसे बड़ा प्रशासनिक काम बन गया है? व्यंग्य में कहा जा सकता है की कलेक्टर बदलते रहे, सरकारें बदलती रहीं, आदेश बदलते रहे...लेकिन कुर्सी नहीं बदली, अब देखना यह है कि 3 अगस्त का नया शासन आदेश इस कुर्सी तक पहुंचता है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ही की आजीवन प्रतिनियुक्ति के ताबूत में आखिरी कील कौन ठोकेगा? क्या विभाग? क्या कलेक्टर? क्या संभाग आयुक्त? क्या शासन? या फिर 15 अगस्त आएगा, तिरंगा फहरेगा और कोरिया कलेक्टरेट की वह पुरानी व्यवस्था उसी कुर्सी पर बैठकर आजादी का जश्न देखेगी?

मत्स्य विभाग का कर्मचारी, लेकिन कलेक्टर कार्यालय में लंबी सेवा—किस नियम से?

प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मूल विभाग से जुड़ा है, उपलब्ध दस्तावेजों और पूर्व में प्रकाशित सामग्री के अनुसार संबंधित कर्मचारी का संबंध मत्स्य महासंघ/मत्स्य विभाग से रहा है, वर्ष 2000 के आसपास मध्यप्रदेश पुनर्गठन के बाद सेवा संबंधी व्यवस्था और विकल्प को लेकर दस्तावेज सामने आए हैं, यहीं से मूल सवाल पैदा होता है, जब कर्मचारी का मूल संबंध मत्स्य क्षेत्र से था तो कलेक्टर कार्यालय में इतने लंबे समय तक स्टेनो के रूप में सेवा किस प्रशासनिक व्यवस्था के तहत जारी रही? यदि प्रतिनियुक्ति थी तो उसकी अवधि क्या थी? यदि अवधि समाप्त हुई तो आगे विस्तार किसने दिया? यदि संविलियन हुआ तो आदेश क्या है? और यदि संविलियन नहीं हुआ तो राजस्व विभाग में लंबे समय तक काम करने की स्थिति किस आधार पर बनी? इन सवालों का जवाब किसी राजनीतिक बयान से नहीं, बल्कि सरकारी फाइल और आदेश से मिलना चाहिए।

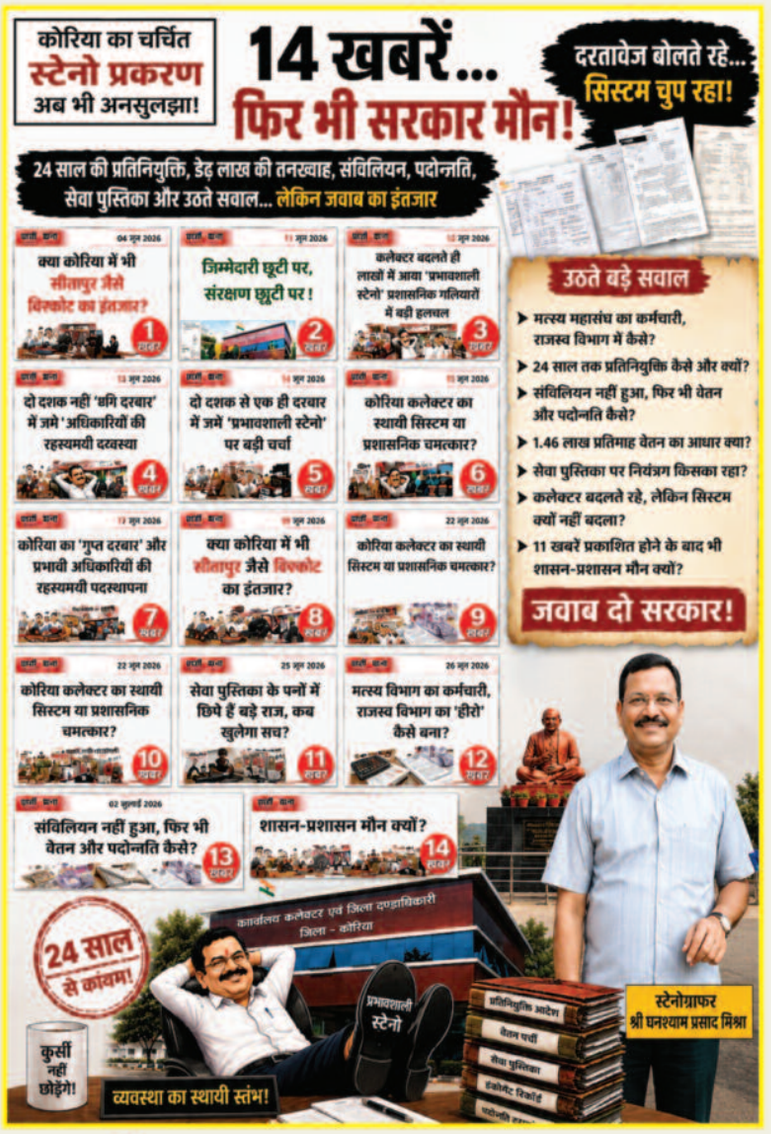

संविलियन का सवाल भी अब फाइलों के कटघरे में...

इस पूरे प्रकरण में संविलियन की चर्चा भी महत्वपूर्ण है, पूर्व में सामने आए दस्तावेजों के आधार पर राजस्व विभाग में संविलियन के प्रयास को लेकर सवाल उठे हैं, लेकिन यहां भी दो ही स्थिति हो सकती है, संविलियन हुआ—तो आदेश सामने आए, संविलियन नहीं हुआ—तो फिर इतने वर्षों तक व्यवस्था किस आधार पर चली? सरकारी सेवा में पद, विभाग, वेतन, वरिष्ठता और सेवा अवधि केवल मौखिक सहमति से तय नहीं होते, इनके पीछे आदेश, नियम और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति होती है, यही कारण है कि अब इस पूरे मामले की सबसे बड़ी मांग किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में फैसला नहीं, बल्कि फाइलों की जांच है।

तीन साल वाली व्यवस्था बनाम 25 साल का सवाल...

अब सबसे बड़ा विरोधाभास यही है, एक तरफ लंबे समय से एक ही शाखा या स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों को स्थानांतरित करने की नीति और आदेशों की चर्चा है, दूसरी तरफ कोरिया कलेक्टर कार्यालय में करीब 25 साल पुरानी व्यवस्था का सवाल खड़ा है, तो क्या नियम सभी के लिए समान हैं? यदि किसी कर्मचारी को तीन वर्ष बाद स्थानांतरण योग्य माना जाता है, तो 25 वर्ष की अवधि किस श्रेणी में आएगी? क्या इसके लिए कोई विशेष अनुमति है? क्या हर अवधि के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली गई? क्या प्रतिनियुक्ति का प्रत्येक विस्तार विधिवत दर्ज है? क्या मूल विभाग ने कर्मचारी की वापसी की मांग की? यदि की तो क्या हुआ? यदि नहीं की तो क्यों नहीं? इन सवालों का जवाब मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामला नियम आधारित विशेष व्यवस्था है या वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक परंपरा।

क्या 15 अगस्त से पहले कलेक्टर कार्यालय भी 25 साल पुरानी प्रतिनियुक्ति से आजाद हो पाएगा?

अब बात 15 अगस्त की, 15 अगस्त भारत की स्वतंत्रता का पर्व है, लेकिन इस बार कोरिया में एक अलग तरह की चर्चा भी है की क्या 15 अगस्त से पहले कलेक्टर कार्यालय भी 25 साल पुरानी प्रतिनियुक्ति से आजाद हो पाएगा? यह सवाल व्यंग्य है, लेकिन इसके पीछे प्रशासनिक गंभीरता छिपी हुई है, यदि शासन मानता है कि व्यवस्था पूरी तरह सही है तो उसे सार्वजनिक रूप से नियम और आदेश सामने रखकर मामला समाप्त कर देना चाहिए, यदि कहीं कोई प्रशासनिक विसंगति है तो जांच कर उसे सुधारना चाहिए, और यदि व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लेना है तो संबंधित कर्मचारी को उसके मूल विभाग में वापस भेजना चाहिए, यानी तीनों रास्ते खुले हैं—स्पष्टीकरण, जांच या सुधार, लेकिन चौथा रास्ता—चुप्पी—सबसे ज्यादा सवाल पैदा करता है।

3 अगस्त का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू-अब कार्रवाई की घड़ी

इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण नया दस्तावेज है—सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का 3 अगस्त 2026 का डेस्क आवंटन में फेरबदल आदेश, शासन ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य के विभिन्न विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, संभागीय आयुक्त कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में कई अधिकारी-कर्मचारी लंबे समय से एक ही स्थान अथवा एक ही कार्य-पटल पर कार्यरत हैं। शासन ने प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यकुशलता और सुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे कार्य-पटल में बदलाव की आवश्यकता बताई है, इसके बाद शासन ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य-पटल का प्रत्येक तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से परिवर्तन किया जाए, यही नहीं, यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी कर्मचारी को उसी कार्य-पटल पर बनाए रखना आवश्यक हो, तो सक्षम प्राधिकारी के लिखित एवं कारणयुक्त अनुमोदन के बाद ही ऐसा किया जा सकता है, यानी अब शासन ने खुद नियम के साथ अपवाद की शर्त भी स्पष्ट कर दी है, शासन ने अपने 3 अगस्त के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया है, इसमें कार्यालय स्तर पर आवश्यक अभिलेख एवं कार्य-पटल परिवर्तन का विवरण संधारित करने का निर्देश भी दिया गया है, इसका अर्थ यह है कि अब हर कार्यालय को यह देखना होगा कि कौन कर्मचारी कितने समय से किस कार्य-पटल पर है, यहीं से कोरिया के मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल निकलता है— क्या कलेक्टर कार्यालय कोरिया भी अपने डेस्क आवंटन का रिकॉर्ड तैयार करेगा? यदि करेगा तो उसमें घनश्याम मिश्रा की स्थिति क्या दर्ज होगी?

अब गेंद शासन के पाले में...

दैनिक घटती-घटना द्वारा लगातार उठाए गए सवालों के बाद अब गेंद पूरी तरह शासन-प्रशासन के पाले में है, खबर गलत है तो खंडन कीजिए, दस्तावेज गलत हैं तो दस्तावेज दिखाइए, व्यवस्था सही है तो नियम बताइए, व्यवस्था गलत है तो कार्रवाई कीजिए, जांच हो चुकी है तो रिपोर्ट बताइए, लेकिन यदि न खंडन होगा, न जांच होगी, न कार्रवाई और न ही स्पष्टीकरण—तो सवाल फिर वही रहेगा कि आखिर 14 खबरों के बाद भी शासन-प्रशासन ने आंखें क्यों मूंद रखी हैं? क्योंकि कलेक्टर बदलते रहे हैं और आगे भी बदलेंगे, सरकारी अधिकारी आते-जाते रहेंगे, पदाधिकारी बदलेंगे, सरकारें भी बदलती रहेंगी, लेकिन किसी एक कर्मचारी की पदस्थापना यदि 25 वर्ष तक एक ही जगह बनी रहती है, तो वह व्यवस्था से जुड़ा सवाल बन जाती है, और शायद इसीलिए इस बार 15 अगस्त के पहले कोरिया में एक अलग सवाल पूछा जा रहा है देश तो आजाद हो गया, अब क्या कोरिया कलेक्टरेट भी 25 साल पुरानी प्रतिनियुक्ति से आजाद होगा? या फिर 15 अगस्त आएगा, झंडा फहरेगा, मिठाई बंटेगी...और फाइल के किसी कोने से वही पुरानी आवाज आएगी या व्यवस्था यथावत रहेगी!

14 खबरों के बाद भी सन्नाटा, आखिर यह कैसी प्रशासनिक चुप्पी?

पत्रकारिता का मूल काम सवाल पूछना है, शासन का काम जवाब देना, लेकिन कोरिया के इस प्रकरण में स्थिति कुछ अलग दिखाई दे रही है, एक-दो खबर होती तो कहा जा सकता था कि मामला ध्यान में नहीं आया होगा, दो-चार सवाल होते तो कहा जा सकता था कि विभागीय स्तर पर परीक्षण चल रहा होगा, लेकिन जब 14 बार दस्तावेजों के आधार पर सवाल उठाए जा चुके हों, तब भी यदि संबंधित विभाग, जिला प्रशासन या शासन की ओर से स्पष्ट तथ्यात्मक जवाब सामने नहीं आता, तो चुप्पी स्वयं एक नया सवाल बन जाती है, यहां सवाल किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का नहीं है, सवाल यह है कि व्यवस्था सही है या नहीं? यदि संबंधित कर्मचारी की वर्षों पुरानी पदस्थापना नियमसम्मत है तो शासन को कहना चाहिए कि किस आदेश और किस नियम के तहत यह व्यवस्था लगातार चली, यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाई गई तो हर विस्तार आदेश कहां है? मूल विभाग से बाहर इतने लंबे समय तक सेवा किस व्यवस्था के तहत जारी रही? खबर गलत है तो खंडन कीजिए, खबर सही है तो जांच कीजिए, जांच हो चुकी है तो रिपोर्ट बताइए, लोकतंत्र में इससे ज्यादा कठिन मांग आखिर है भी क्या?

CMYK

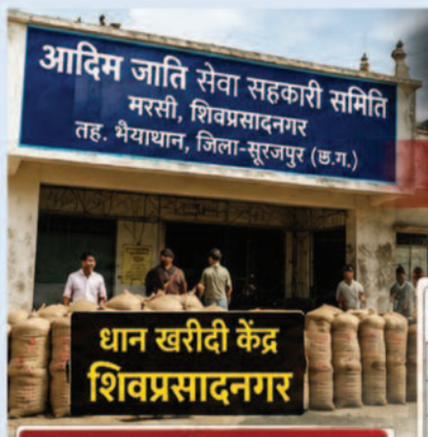

धान खरीदी से जमीन तक पहुंचा खेल!

शिवप्रसादनगर समिति में रिकॉडों का बड़ा खुलासा

205 क्विंटल धान की खरीदी किसके नाम?

हदीश अंसारी, साधना कुशवाहा, रिजवान और मोहम्मद सोहराब के नाम की कड़ियां जांच के घेरे में

धान खरीदी केंद्र शिवप्रसादनगर

7.7 एकड़ जमीन का मामला

ग्राम- सोनपुर (00005),
तहसील- भैयाथान
जिला- सूरजपुर

पहले भूमि स्वामी
जरीफ उल्ला

अब दर्ज भू-स्वामी
हदीश मोहम्मद, रिजवान अंसारी, साधना कुशवाहा

14 खसरों की जमीन, कुल रकबा लगभग 3.13 है. (करीबा (करीब 7.7 एकड़)

खसरा नंबर	रकबा (हे.)	खसरा नंबर	रकबा (हे.)
397	0.3100	595/7	0.0500
398/1	0.4800	596/1	0.2000
496/2	0.3300	596/2	0.2000
497/1	0.1400	672/1	0.8600
591/3	0.1900	673/2	0.0800
595/1	0.1000	677/1	0.0700
595/6	0.0500	686	0.0700
कुल रकबा	3.13 हे. (करीब 7.7 एकड़)		

खसरा 188/2 (राजस्व रिकॉर्ड): रकबा- 0.6000 हे. भू-स्वामी/कब्जेदार हदीश मोहम्मद मोहम्मद सोहराब

फसल रिकॉर्ड 2024-25: खसरा 188/2, 0.6000 हे. धान दर्ज खातेदार- हदीश मोहम्मद मोहम्मद सोहराब

फसल रिकॉर्ड 2025-26: खसरा 188/2, 0.6000 हे. धान दर्ज खातेदार- हदीश मोहम्मद मोहम्मद सोहराब

PACS शिवप्रसादनगर से बैंक संबंध 01-05-2025 से

205 क्विंटल धान का बड़ा सवाल

- फसल बोई गई: अगस्त 2025
- जमीन बिक्री: नवंबर 2025
- DCS सत्यापन: हां (रिकॉर्ड में दर्ज)
- 205 क्विंटल धान खरीदी: शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र

? फसल बोया किसी और ने धान बेचा किसके नाम ? ?

आयकर विभाग ने हदीश अंसारी के खातों पर रोक लगाई, फिर पैसे कहां से आएं ?

धान खरीदी से जमीन तक पहुंचा 'सहकारिता' का कनेक्शन! शिवप्रसादनगर में 7.7 एकड़ भूमि खरीदी के बाद भंवराही 1.5 एकड़ भूमि खरीदी ने बढ़ाई हलचल

धान की खरीदी,जमीन की रजिस्ट्री और समिति के चेहरे-शिवप्रसादनगर में 'कनेक्शन' का रहस्य गहराया

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/भैयाथान,13 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। सहकारिता विभाग का उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से बचाना है,लेकिन सूरजपुर जिले के भैयाथान क्षेत्र की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति शिवप्रसादनगर से जुड़े दस्तावेजों को देखकर ऐसा लगता है कि यहां कहानी कुछ उलटी चल रही है, किसान को अपनी फसल बेचने के लिए नियमों की लंबी कतार पार करनी पड़ती है, जबकि जमीन,फसल और समिति से जुड़े नामों की कड़ियां सामने आने पर सवाल यह उठता है कि कहीं व्यवस्था के दरवाजे कुछ लोगों के लिए अपेक्षाकृत आसान तो नहीं हैं? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उपलब्ध दस्तावेजों में एक ओर भूमि रिकॉर्ड में हदीस मोहम्मद और मोहम्मद सोहराब जैसे नाम दिखाई देते हैं, दूसरी ओर उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण में साधना कुशवाहा और रिजवान को धान खरीदी व्यवस्था से जुड़ा बताया गया है,और इसी पृष्ठभूमि में जमीन की खरीद-बिक्री तथा धान खरीदी के रिकॉर्ड को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, व्यंग्य यही है कि किसान अगर एक बोरा धान में नमी ज्यादा कर दे तो व्यवस्था की नजरें तेज हो जाती हैं, लेकिन जमीन, फसल और समिति से जुड़े रिकॉर्ड एक साथ दिखाई दें तो वही व्यवस्था अचानक चश्मा उतारकर बैठ जाती है!

कहानी धान की है या जमीन की?

शिवप्रसादनगर समिति को लेकर उठ रहे सवालों का केंद्र अब सिर्फ धान खरीदी नहीं रहा, मामला जमीन के रिकॉर्ड तक पहुंच गया है,उपलब्ध रिकॉर्ड में ग्राम भंवराही,तहसील भैयाथान,जिला सूरजपुर के खसरा नंबर 188/2 का रकबा 0.6000 हेक्टेयर दर्ज है,रिकॉर्ड में संबंधित खातेदारों में हदीस मोहम्मद और मोहम्मद सोहराब के नाम दिखाई देते हैं, यानी जमीन के रिकॉर्ड ने खुद एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसे अब किसी राजनीतिक बयान या मौखिक आरोप से दबाया नहीं जा सकता, और मजेदार बात यह है कि यही रिकॉर्ड पीएसीएस शिव प्रसादनगर से संबंधित बैंक विवरण भी दिखाता है तथा उसमें 01 मई 2025 से संबंधित बैंक कनेक्शन का उल्लेख है, अब सवाल यह है कि जमीन का मालिक कौन,फसल किसकी,किसान पंजीयन किसका और समिति से संबंध किसका? अगर सब कुछ सामान्य है तो जवाब देने में दिक्कत कैसी?

खसरा 188/2 की कहानी में धान भी है और नाम भी...

उपलब्ध कृषि रिकॉर्ड में खसरा 188/2, रकबा 0.6000 हेक्टेयर तथा संबंधित कृषि विवरण दर्ज हैं,रिकॉर्ड में हदीस मोहम्मद और सोहराब से जुड़े नाम दिखाई देते हैं, एक अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड में भी इसी खसरे का रकबा 0.6000 हेक्टेयर दर्ज है और ग्राम, तहसील तथा जिला विवरण शिवप्रसादनगर-भैयाथान-सूरजपुर से संबंधित है,अब यहां पत्रकारिता का सबसे सरल सवाल खड़ा होता है–अगर जमीन सामान्य है तो उसकी जांच सामान्य तरीके से कर दीजिए,अगर धान सामान्य है तो उसकी खरीदी का रिकॉर्ड दिखा दीजिए,और अगर समिति की भूमिका सामान्य है तो समिति की पूरी कार्यवाही सामने रख दीजिए,फिर आखिर परेशानी किस बात की?

समिति प्रभारी और खरीदी प्रभारी के साथ जमीन संयोग कितना बड़ा है?

उपलब्ध जानकारी में साधना कुशवाहा और रिजवान को धान खरीदी प्रभारी तथा मोहम्मद सोहराब को समिति प्रभारी बताया गया है,इसी पृष्ठभूमि में हदीस अंसारी के साथ जमीन के सह-स्वामित्व अथवा खरीद-बिक्री के संबंध सामने आने की बात कही जा रही है,यहां भी सवाल जमीन खरीदने के अधिकार पर नहीं है,कोई भी पात्र व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, असली सवाल है–क्या धान खरीदी व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति और धान कारोबार से जुड़े बताए जा रहे व्यक्ति के बीच संपत्ति संबंध हैं? अगर हैं तो–क्या विभाग को इसकी जानकारी थी? क्या किसी स्तर पर हितों के टकराव की जांच हुई? क्या संबंधित व्यक्तियों की संपत्ति और आय के स्रोत का परीक्षण हुआ? क्या खरीदी अवधि और जमीन खरीद की तारीखों का मिलान किया गया? अगर नहीं हुआ तो फिर सहकारिता की निगरानी व्यवस्था आखिर कर क्या रही थी?

7.7 एकड़ जमीन ने क्यों बढ़ाई बेचैनी?

पूर्व मामले में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ग्राम सोनपुर की करीब 3.13 हेक्टेयर यानी 7.7 एकड़ कृषि भूमि के संबंध में हदीस मोहम्मद,रिजवान अंसारी और साधना कुशवाहा के नाम सामने आने की बात कही गई है, बताए गए खसरों में 397,398/1,496/2,497/1,591/3,595/1, 595/6,595/7,596/1,596/2,672/1,673/2,677/1 और 686 शामिल हैं, यहां फिर वही व्यंग्य लौटता है किसान की जमीन अगर दो नामों में हो तो राजस्व रिकॉर्ड में सवाल,तीन नामों में हो तो दस्तावेज,लेकिन समिति से जुड़े लोगों और धान कारोबार से जुड़े व्यक्ति के नाम एक साथ दिखें तो इसे जांचने के लिए शायद एक और समिति बनानी पड़े! भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य रजिस्ट्री और स्थानीय दरों से ही निर्धारित होगा,इसलिए इसे सीधे करोड़ों की संपत्ति कहना उचित नहीं होगा, लेकिन 7.7 एकड़ कृषि भूमि का एक साथ कई नामों में जाना अपने आप में इतना बड़ा तथ्य जरूर है कि संबंधित रजिस्ट्री,भुगतान और नामांतरण की जांच की जाए।

धान बोया किसने और खरीदा किसने-205 क्विंटल का सवाल...

इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी 205 क्विंटल धान से जुड़ी बताई जा रही है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार फसल की बुआई अगस्त 2025 में हुई और जमीन का विक्रय नवंबर 2025 में हुआ, इसके बाद किसान सूचना पोर्टल में फसल सत्यापन/प्राप्ति संबंधी प्रविष्टि दिखाई देने और 205 क्विंटल धान शिवप्रसादनगर खरीदी केंद्र में नए भू-स्वामियों के नाम से खरीदे जाने का दावा है,यदि रिकॉर्ड की तारीखें यही हैं,तो सवाल बिल्कुल सीधा है-जिस समय फसल बोई गई थी, उस समय जमीन किसके नाम थी? और उसके बाद—धान बेचने का अधिकार किस आधार पर तय हुआ? यहां किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना उद्देश्य नहीं है,लेकिन किसान पंजीयन,भूमि रिकॉर्ड,फसल पंजीयन,डीसीएस सत्यापन,धान खरीदी और भुगतान की तारीखों का मिलान होना चाहिए,क्योंकि सरकारी पोर्टल में तारीखें केवल सजावट के लिए नहीं होतीं।

हदीस अंसारी की पकड़ का सवाल भी यहीं से उठता है...

क्षेत्र में हदीस अंसारी को लेकर धान कारोबार में प्रभावशाली व्यक्ति होने के आरोप लगाए जाते रहे हैं,आरोप यह भी है कि उनके प्रभाव के अनुसार कुछ समितियों में समिति प्रबंधक और धान खरीदी प्रभारी की भूमिका प्रभावित होती रही,ये आरोप हैं, प्रमाणित निष्कर्ष नहीं,लेकिन यदि किसी व्यक्ति को लेकर वर्षों से ऐसी चर्चा है और उसी व्यक्ति का नाम समिति से जुड़े लोगों के साथ भूमि रिकॉर्ड में सामने आता है,तो विभाग के लिए जांच करना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए,आखिर सहकारिता विभाग के पास रिकॉर्ड हैं,कौन समिति में है? कौन खरीदी प्रभारी है? किसने किसान पंजीयन किया? किसने सत्यापन किया? किसके हस्ताक्षर हैं? किसके खाते में भुगतान हुआ? किसके नाम जमीन है? बस फाइल खोलनी है।

आयकर विभाग की कार्रवाई का दावा–फिर जमीन खरीद का धन कहां से आया?

इस पूरे प्रकरण में एक और गंभीर आरोप यह है कि हदीस अंसारी के बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद लेनदेन पर रोक लगी थी और उनसे बड़ी राशि की रिकवरी का मामला था,इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि के लिए आयकर विभाग के आदेश,बैंक रिकॉर्ड और संबंधित कार्रवाई के दस्तावेज देखना आवश्यक है,उपलब्ध कृषि दस्तावेज अकेले इस दावे को प्रमाणित नहीं करते,लेकिन यदि ऐसा आदेश वास्तव में मौजूद है, तो फिर भूमि खरीद के समय भुगतान का स्रोत जांच का बेहद महत्वपूर्ण विषय बन जाता है,रजिस्ट्री में पैसा कहां से आया? किस बैंक खाते से गया? किसने भुगतान किया? क्या भुगतान बैंकिंग माध्यम से हुआ? क्या किसी तीसरे व्यक्ति के खाते का इस्तेमाल हुआ? ये सवाल आयकर और प्रवर्तन से जुड़े रिकॉर्ड से आसानी से जांचे जा सकते हैं।

सहकारिता विभाग के लिए सबसे असहज सवाल...

सहकारिता व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक निगरानी की व्यवस्था है, संभागीय स्तर से लेकर जिला और समिति स्तर तक अधिकारी मौजूद हैं,फिर यदि किसी समिति में लगातार धान खरीदी में अनियमितता के आरोप,धान शॉर्टेज के सवाल, परिवहन रिकॉर्ड पर सवाल,किसान पंजीयन पर सवाल,समिति कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल और अब जमीन के लेनदेन से जुड़े सवाल एक साथ उठ रहे हैं,तो यह पूछना जरूरी है कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने क्या देखा? क्या उन्होंने केवल रजिस्टर देखा? अगर हां, तो रजिस्टर में सब ठीक मिला होगा,लेकिन जमीन का रिकॉर्ड रजिस्टर के बाहर भी होता है, यही वह जगह है जहां सरकारी फाइल और जमीन की मिट्टी आमने-सामने खड़ी हो जाती है।

घटती घटना | कोरिया समाचार | अम्बिकापुर सोमवार 03 अगस्त 2026 | 6

भाग-1

पशुपालन ऋण से धान शॉर्टेज तक: सहकारिता तंत्र का खेल या संरक्षण का मेल?

एफआईआर, सेवा समाप्ति, धान खरीदी में कमी और 7.7 एकड़ संयुक्त भूमि ने खड़े किए कई गंभीर सवाल, दस्तावेजों के आधार पर उठी निष्पक्ष जांच की मांग

क्या यह सिर्फ संयोग है?

जेल,बर्खास्तगी और फिर 7.7 एकड़ जमीन! सहकारिता तंत्र में कौन देता रहा संरक्षण?

पशुपालन ऋण से धान शॉर्टेज तक आखिर किसके संरक्षण में फलता-फूलता रहा सहकारिता का खेल?

एफआईआर,बर्खास्तगी,फिर बढ़ती संपत्ति! भैयाथान की समितियों पर आखिर किसका था संरक्षण?

पहला अध्याय - सोनपुर समिति से शुरू हुआ विवाद

एफआईआर दर्ज, मामला पहुंचा न्यायालय

सेवा समाप्ति का आदेश

घटती घटना | कोरिया- सूरजपुर समाचार | अम्बिकापुर शनिवार 08 अगस्त 2026 | 5

भाग-2

जेल से जमानत, बर्खास्तगी के बाद बढ़ती संपत्ति! 7.7 एकड़ जमीन और नई Creta के पीछे आखिर किसका संरक्षण?

सबसे बड़े सवाल

सहकारिता व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल... अब वक्त है निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच का!

जेल,बर्खास्तगी और फिर 7.7 एकड़ जमीन! आखिर कहां से आई बढ़ती संपत्ति,कौन करेगा निष्पक्ष जांच?

एफआईआर से संयुक्त भूमि तक: सहकारिता तंत्र पर उठे नए सवाल,क्या होगी निष्पक्ष जांच?

धान शॉर्टेज के बाद क्या बदली जांच की दिशा?

निलंबन हुआ,अब पुनर्बहाली की चर्चाएं

क्यों जरूरी है स्वतंत्र जांच?

आज भी कई प्रश्न अनुत्तरित हैं...

कागजों में धान चलता है,जमीन पर पैसा चलता है-बीच में किसान कहां है?

सहकारी समिति की व्यवस्था में कागजों का महत्व बहुत है,लेकिन जब कागजों में एक किसान,जमीन के रिकॉर्ड में दूसरा नाम और धान खरीदी में तीसरा नाम दिखाई दे तो सवाल उठता है कि व्यवस्था किसे किसान मानती है? आम किसान को अपनी जमीन,फसल,पंजीयन,आधार,बैंक खाता और दस्तावेज लेकर घूमना पड़ता है,लेकिन यदि किसी मामले में जमीन का स्वामित्व बदलने के बाद फसल संबंधी रिकॉर्ड भी नए नामों के साथ जुड़ता दिखाई दे,तो सवाल पूछना स्वाभाविक है,कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान के लिए नियम लोहे की सलाख हैं और प्रभावशाली लोगों के लिए वही नियम रबर की पट्टी?

धान शॉर्टेज और जमीन खरीद-दोनों का आपस में संबंध है या महज संयोग?

शिवप्रसादनगर समिति को लेकर धान की कमी और शॉर्टेज से संबंधित आरोप भी सामने आते रहे हैं,यदि वास्तव में किसी सीजन में धान की बड़ी कमी हुई है तो उसकी जांच के लिए खरीदी से लेकर मिलर तक पूरा स्टॉक ट्रैक किया जाना चाहिए, और यदि उसी अवधि में समिति तथा धान खरीदी व्यवस्था से जुड़े लोगों के नाम पर बड़ी भूमि खरीद होती है,तो दोनों घटनाओं को कम से कम जांच के दौरान एक साथ रखकर देखना चाहिए,यह कहना कि धान की कमी का पैसा जमीन में लगा,बिना वित्तीय जांच के उचित नहीं होगा,लेकिन यह पूछना पूरी तरह उचित है कि–क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई वित्तीय संबंध है?

शिवप्रसादनगर में रिकॉर्ड कुछ और कहानी कह रहे,सवाल कुछ और–हदीस मोहम्मद,साधना कुशवाहा,रिजवान और मोहम्मद सोहराब के नामों की कड़ियां जांच के घेरे में...

धान खरीदी से जमीन तक पहुंची 'सहकारिता' की कहानी,शिवप्रसादनगर में हदीस अंसारी और समिति से जुड़े नामों ने बढ़ाए सवाल...

समिति प्रभारी,धान खरीदी प्रभारी और हदीस अंसारी के बीच जमीन की साझेदारी? सहकारिता विभाग की भूमिका पर उठे सवाल

किसान के धान पर नियमों की पहरेदारी,जमीन के सौदों पर 'सहकारिता' की मेहरबानी?

धान का हिसाब पूछो तो फाइल बंद, जमीन का हिसाब देखो तो नाम ही नाम–शिवप्रसादनगर में सहकारिता का नया गणित

धान किसान का,जमीन साझीदारों की–शिवप्रसादनगर समिति में कागजों ने खोली 'सहकारिता' की पोल...

धान खरीदी केंद्र से जमीन की रजिस्ट्री तक पहुंचा कनेक्शन, शिवप्रसादनगर में सहकारिता विभाग की चुप्पी पर तंज

धान खरीदी से जमीन तक पहुंचा 'सहकारिता' का कनेक्शन! शिवप्रसादनगर में 7.7 एकड़ भूमि, 205 क्विंटल धान और समिति से जुड़े नामों ने खड़े किए गंभीर सवाल

हदीस अंसारी,समिति प्रभारी मोहम्मद सोहराब तथा धान खरीदी प्रभारी बताए जा रहे साधना कुशवाहा-रिजवान के बीच जमीन के लेनदेन की कड़ियां जांच के घेरे में,जमीन रिकॉर्ड ने बढ़ाई हलचल

अब जांच सिर्फ समिति की नहीं,पूरी चेन की होनी चाहिए...

अगर प्रशासन सचमुच इस मामले की तह तक जाना चाहता है तो केवल समिति प्रबंधक से जवाब मांगना पर्याप्त नहीं होगा,जांच में राजस्व रिकॉर्ड,रजिस्ट्री,नामांतरण,किसान पंजीयन,किसान सूचना पोर्टल,डीसीएस सत्यापन,खरीदी रजिस्टर,स्टॉक रजिस्टर,परिवहन दस्तावेज,बैंक भुगतान और संबंधित खातों का मिलान होना चाहिए, साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि जमीन खरीद की रकम किस माध्यम से दी गई,खासकर खसरा 188/2 के मामले में उपलब्ध रिकॉर्ड में 0.6000 हेक्टेयर भूमि तथा हदीस मोहम्मद और मोहम्मद सोहराब से संबंधित विवरण सामने आते हैं,दूसरी ओर रिकॉर्ड में पीएसीएस शिवप्रसादनगर से संबंधित बैंक कनेक्शन भी दर्ज है, अब विभाग को केवल इतना बताना है कि इन रिकॉर्डों की वास्तविक प्रशासनिक स्थिति क्या है।

सवालों की फसल खूब है, अब जवाब की कटाई कब होगी?

शिवप्रसादनगर समिति की कहानी फिलहाल ऐसी फसल बन गई है जिसमें धान से ज्यादा सवाल उग आए हैं,एक तरफ 7.7 एकड़ जमीन, दूसरी तरफ 205 क्विंटल धान,एक तरफ हदीस मोहम्मद का नाम,दूसरी तरफ साधना कुशवाहा और रिजवान के नाम, एक तरफ समिति प्रभारी मोहम्मद सोहराब, दूसरी तरफ खसरा 188/2 का रिकॉर्ड,और बीच में सहकारिता विभाग की निगरानी व्यवस्था, अब यदि यह सब सामान्य है तो इससे अच्छी खबर क्या होगी? विभाग बस दस्तावेज सार्वजनिक कर दे,बताए–जमीन कब खरीदी गई? किसने खरीदी? पैसा किसने दिया? फसल किसने बोई? किसके नाम पंजीयन हुआ? डीसीएस ने किसका सत्यापन किया? 205 क्विंटल किसके नाम खरीदा गया? भुगतान किसे हुआ? और समिति से जुड़े व्यक्तियों की जमीन खरीद का धान खरीदी से कोई संबंध है या नहीं? इतने सवालों के जवाब मिल जाएं तो व्यंग्य भी समाप्त और कहानी भी समाप्त।

सबसे बड़ा सवाल : संयोगों की संख्या इतनी ज्यादा कैसे हो गई?

किसी एक व्यक्ति का जमीन खरीदना सामान्य है,किसी समिति कर्मचारी का जमीन खरीदना भी सामान्य है,किसी किसान के नाम फसल दर्ज होना भी सामान्य है,धान खरीदी होना भी सामान्य है,लेकिन जब जमीन,फसल,समिति, खरीदी प्रभारी,समिति प्रभारी और धान कारोबार से जुड़े बताए जा रहे व्यक्ति एक ही कहानी के अलग-अलग पन्नों पर बार-बार दिखाई दें,तब पत्रकारिता का काम निष्कर्ष सुनाना नहीं बल्कि फाइल खोलने का सवाल करना है,और फिलहाल शिवप्रसादनगर में यही सवाल सबसे बड़ा है—यह सिर्फ संयोगों की कहानी है या सहकारिता के भीतर किसी बड़े गठजोड़ की? इसका जवाब कागजों से ही निकलेगा—और इस बार कागजों को बोलना पड़ेगा।

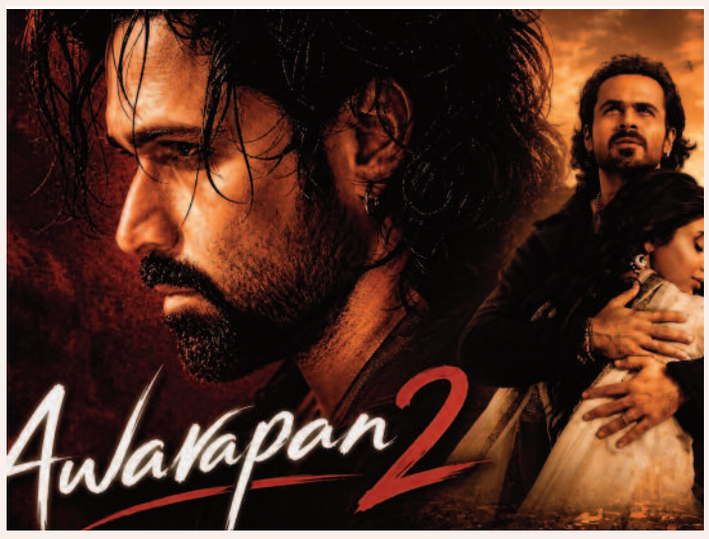

आवारापन 2 ने रिलीज से पहले ही रचा इतिहास

एडवांस बुकिंग के दौरान 18 घंटे में बिके 1.3 लाख टिकट

फिल्म आवारापन 2 ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पहले पार्ट आवारापन के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

नई दिल्ली। आवारापन 2 की अनाउंसमेंट ने इसके कुछ पुराने फैंस के जख्म हरे कर दिए थे। वे दोबारा से फिर वहीं जादू को पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। इसका परिणाम भी हमको अब फिल्म की एडवांस बुकिंग में देखने को मिल गया।

कितना था पार्ट 1 का कलेक्शन?

साल 2007 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। विशेष फिल्म्स की इस महत्वाकांक्षी फिल्म अपनी पूरी कमाई के दौरान सिर्फ 7.7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

लेकिन समय के साथ, जैसे-जैसे दर्शकों ने इसे होम मीडिया,केबल और बाद में स्ट्रीमिंग पर देखा, तो यहां से आवारापन को कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला। वही देर से मिली पहचान और प्यार अब इसके सीक्वल को फायदा पहुंचा रहा है, जो इस हफ्ते के आखिर में रिलीज होने वाला है।

एडवांस बुकिंग में ही कर दिया कमाल

आवारापन 2 आने वाले 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। के 2026 में बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक होने की उम्मीद है। फिल्म को लेकर इतनी जबरदस्त चर्चा है कि इसकी एडवांस बुकिंग देखकर लग रहा है कि यह रिलीज से पहले ही अपने पहले पार्ट की कुल कमाई का आंकड़ा पार कर सकती है।

आवारापन 2 की एडवांस बुकिंग रिलीज से सिर्फ 48 घंटे पहले शुरू हुई और बुधवार को इसे जबरदस्त शुरुआत मिली। 13 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक यानी फिल्म के रिलीज होने से सिर्फ 18 घंटे पहलेआवारापन 2 के रिलीज वाले दिन के लिए 1.3 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके थे।

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अपने ओपनिंग डे के लिए 4 करोड़ के टिकट बेचे हैं। ट्रेड जानकारों का अनुमान है कि फिल्म के ओपनिंग वीकेंड और उसके बाद की कुल एडवांस बुकिंग 9 करोड़ ग्रॉस (यानी 7 से 8 करोड़ नेट) से ज्यादा है। इसका मतलब है कि रिलीज से पहले ही आवारापन 2 ने अपनी पिछली फिल्म की कुल कमाई के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

डबल डिजिट में करेगी ओपनिंग

आवारापनने रिलीज के पहले दिन 79 लाख की कमाई की थी और अपने पहले वीकेंड में 2.88 करोड़ रुपये कमाए थे। ये आंकड़ा काफी कम था। इसके उलट, %आवारापन 2% इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म साबित हो सकती है। फिल्म पहले दिन ही 20 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लेगी।

इंटिमेट सीन के बाद आमिर और पूजा के बीच छाई चुप्पी

बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा बेदी ने अभिनेता आमिर खान के साथ अपने रिश्ते को लेकर वर्षों से चल रही अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है। दोनों कलाकार वर्ष 1992 में रिलीज हुई फिल्म 'जो जीता वही सिकंदर' में साथ नजर आए थे। फिल्म की रिलीज के दौरान ऐसी चर्चाएं हुई थीं कि आमिर और पूजा एक-दूसरे के प्रति आकर्षित थे। अब अभिनेत्री ने इन चर्चाओं को मजाक बताते हुए खारिज कर दिया है। पूजा बेदी ने पत्रकार विकी लालवानी से बातचीत के दौरान आमिर खान से जुड़े कई पुराने अनुभव साझा किए। जब उनसे पूछा गया कि क्या 'जो जीता वही सिकंदर' की शूटिंग के दौरान वह और आमिर एक-दूसरे के प्रति आकर्षित थे, तो अभिनेत्री ने हंसते हुए कहा कि यह सवाल ही मजाक जैसा है। उनके जवाब से साफ हुआ कि दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ता होने की चर्चाओं में कोई सच्चाई नहीं थी।

मंसूर खान के निर्देशन में बनी 'जो जीता वही सिकंदर' बॉलीवुड की चर्चित फिल्मों में शामिल है। फिल्म में आमिर खान ने संजयलाल शर्मा और पूजा बेदी ने देविका की भूमिका निभाई थी। फिल्म की कहानी, संगीत और साइकिल रेस के दृश्य आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं।

आतंक ही आतंक के लिए शूट किया था सीन

इसी बातचीत के दौरान पूजा बेदी ने आमिर खान के साथ एक दूसरी फिल्म से जुड़ा किस्सा सुनाया। अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म 'आतंक ही आतंक' के लिए उन्होंने आमिर के साथ एक भावनात्मक और अंतरंग दृश्य शूट किया था। हालांकि बाद में उस दृश्य को फिल्म के अंतिम संस्करण में शामिल नहीं किया गया।

वर्ष 1995 में रिलीज हुई 'आतंक ही आतंक' में आमिर खान, रजनीकांत, जूही चावला और अर्चना जोगलेकर समेत कई कलाकार नजर आए थे। पूजा बेदी ने इस फिल्म में कैमियो किया था। उनके मुताबिक आमिर के साथ शूट किया गया दृश्य कहानी का हिस्सा था, लेकिन एडिटिंग के दौरान उसे हटा दिया गया। अभिनेत्री ने बताया कि यह दृश्य मुंबई फिल्म सिटी के पास स्थित एक बंगले में फिल्माया गया था। उस दौर में शूटिंग की सुविधाएं आज की तरह विकसित नहीं थीं। कलाकारों के लिए अलग-अलग वैनिटी वैन और निजी स्थानों की व्यवस्था आम नहीं थी। शूटिंग पूरी होने के बाद कलाकारों को उसी लोकेशन पर बने कमरों में इंतजार करना पड़ता था।

कमरे में छा गई थी अजीब चुप्पी

पूजा के अनुसार, अंतरंग दृश्य की शूटिंग के बाद उन्हें और आमिर खान को एक कमरे में इंतजार करने के लिए कहा गया। कमरे में एक पलंग था और दरवाजा बंद था। पूजा उस समय काफी युवा थीं और ऐसे दृश्य की शूटिंग के बाद असहज तथा घबराई हुई महसूस कर रही थीं। अभिनेत्री ने कहा कि उनके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। फिल्म उद्योग के बारे में सुनी गई बातों के कारण वह सोच रही थीं कि अब आगे क्या होगा। आमिर और पूजा दोनों कमरे में चुपचाप बैठे थे। दोनों के बीच ऐसी खामोशी छा गई थी,जिससे पूजा की घबराहट और बढ़ गई।

आमिर ने चेस खेलने का दिया सुझाव

पूजा बेदी ने बताया कि आमिर खान ने स्थिति को समझते हुए बातचीत शुरू की। उन्होंने पूजा से पूछा कि क्या वह चेस खेलना पसंद करेंगी। पूजा ने तुरंत इसके लिए हामी भर दी। इसके बाद कमरे में चेस मंगवाया गया और दोनों कलाकार खेल में व्यस्त हो गए। पूजा के अनुसार, आमिर के इस सहज सुझाव से कमरे में बनी असहजता खत्म हो गई और वह सामान्य महसूस करने लगीं। अभिनेत्री का यह खुलासा सोशल मीडिया पर चर्चा में है। प्रशंसक आमिर के व्यवहार और पूजा की स्पष्टवादिता पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पूजा बेदी लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वह सामाजिक और मनोरंजन जगत से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। आमिर खान के साथ पुराने रिश्ते की अफवाहों को खारिज करते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों के बीच हमेशा पेशेवर संबंध रहे।

श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी पर प्रियंका ने दिया सरप्राइज

सुपरस्टार एक्ट्रेस की बायोग्राफी की दिखाई पहली झलक

श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने दिग्गज अभिनेत्री की पहली झलक शेयर करके उनके चाहने वालों को इमोशनल कर दिया है। इंडियन सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी की आज बर्थ एनिवर्सरी है। 13 अगस्त को जन्मी एक्ट्रेस ने लंबे समय तक बॉलीवुड पर रूल किया। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा ने दिग्गज अभिनेत्री की मोस्ट अवेटेड बायोग्राफी की पहली झलक को शेयर किया।

प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की श्रीदेवी की बायोग्राफी की पहली झलक

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट सलिब्रेटेड अदाकारा श्रीदेवी की बायोग्राफी की पहली झलक देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए बताया कि उसका काम कहां तक पहुंचा है। श्रीदेवी की बायोग्राफी में उनकी जिंदगी और करियर के वह अनसुने किस्से फैंस को पढ़ने को मिल सकते हैं, जिसके बारे में शायद उनके चाहने वालों को न पता हो। सुपरस्टार एक्ट्रेस की बायोग्राफी के कवरपेज की फोटो बेवॉच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसका टाइटल है,एम्प्रेस-द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑफ श्रीदेवी- असीम प्रतिभा की मिसाल। अमिताभ बच्चन,धीरज यू कुमार। स्टोरी पर कवर पेज की फोटो शेयर करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने कैप्शन में लिखा, द वन एंड ओनली। आपकी बहुत याद आती है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीदेवी की एम्प्रेस- जल्द आ रही है।

2023 में श्रीदेवी की बायोग्राफी की हुई थी घोषणा

प्रियंका चोपड़ा के इस पोस्ट को श्रीदेवी के पति और प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर किया। साल 2023 में वेस्टलैंड बुक्स ने श्रीदेवी की ऑफिशियल बायोग्राफी लिखने की घोषणा की थी, जिसका टाइटल था,श्रीदेवी : द लाइफ ऑफ अ लीजेंड। इस बुक में 1980 से 1990 के उस दौर के बारे में भी लिखा जाएगा, जब एक्ट्रेस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थीं। श्रीदेवी की बायोपिक लिखने की जिम्मेदारी धीरज कुमार ने उठाई है, जो इस बुक से बतौर ऑथर डेब्यू कर रहे हैं। धीरज वह शख्स हैं, जिन्हें श्रीदेवी अपने परिवार का ही एक हिस्सा मानती थीं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को 54 साल की उम्र में हुआ था। जब वह दुबई में एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने गई थीं,उस दौरान ही उनके निधन की खबर सामने आई थी। दिग्गज अभिनेत्री ने अपने पूरे करियर में मिस्टर इंडिया, चांदनी, चालबाज, हिम्मतवाला जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं।

खेल समाचार

भारत की यू-17 महिला टीम ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के खिलाफ़ दो दोस्ताना मैच खेलने के लिए तैयार

नई दिल्ली,13 अगस्त 2026। एएफसी यू-17 महिला एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर की तैयारी के तहत, भारत की 17 महिला टीम उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में यूएफ ए नेशनल फुटबॉल सेंटर में उज़्बेकिस्तान के खिलाफ़ 27 और 30 अगस्त, 2026 को दो फ्रेंडली मैच खेलेगी। ये दोनों मैच बिना दर्शकों के खेले जाएंगे।इन दो मैचों से हेड कोच जोआकिम अलेक्जेंडरसन को 5 से 11 अक्टूबर तक होने वाले क्वालिफायर से पहले टीम का आकलन करने का मौका मिलेगा। एआईएफएफ मीडिया की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार,भारत को मेज़बान मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ ग्रुप ई में रखा गया है। उज़्बेकिस्तान में होने वाले फ्रेंडली मैचों के बारे में एआईएफएफ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एम सत्यनारायण ने कहा,पिछले साल,हमारी यू-17 महिला टीम ने पहली बार मेरिट के आधार पर एएफसी यू-17 महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया और क्वार्टर-फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। हम उसी लय को बनाए रखना चाहते हैं। यह ज़रूरी है कि लड़कियों को फ्रेंडली मैचों में अच्छी टीमें खेलने को मिलें, ताकि वे बेहतर होती रहें, कीमती अनुभव हासिल करें और क्वालिफायर के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। हमारा लक्ष्य फिर से एशियन कप के लिए क्वालिफाई करना और उम्मीद है कि अगले साल के टूर्नामेंट में एक कदम और आगे बढ़ना है।

तिथि संघवी ने दो गोल्ड मेडल जीतकर सीबीएसई नेशनल्स के लिए क्वालिफाई किया...

नवी मुंबई,13 अगस्त 2026। नवी मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन स्कूल, कोपरखैरणे की 12वीं कक्षा की छात्रा तिथि संघवी ने कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सीबीएसई क्लस्टर एथलेटिक्स मीट 2026-27 में दो इवेंट्स में चैंपियन बनकर सीबीएसईनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026-27 के लिए क्वालिफाई किया है। तिथि ने अंडर-19 गर्ल्स शॉट पुट और अंडर-19 गर्ल्स डिस्कस थ्रो,दोनों में पहला स्थान हासिल किया। इस तरह उन्होंने क्लस्टर लेवल पर डबल गोल्ड मेडलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया और सीबीएसई नेशनल्स में अपनी जगह पक्की की। उनकी यह उपलब्धि इस साल के उनके शानदार स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में एक और कामयाबी है।

तिथि के प्रदर्शन के साथ-साथ, 12वीं कक्षा के ही छात्र सिद्धांत सालियन ने सीबीएसई क्लस्टर एथलेटिक्स मीट 2026-27 में अंडर-19 बॉयज़ 400-मीटर रेस में तीसरा

स्थान हासिल किया। तिथि ने अपनी पढ़ाई और कड़ी एथलेटिक ट्रेनिंग के बीच लगातार संतुलन बनाए रखा है। उन्होंने पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, दोनों में बेहतर करने के लिए ज़रूरी अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।उनका सफर यह दिखाता है कि स्कूल छात्रों को उनकी पढ़ाई के लक्ष्यों के साथ-साथ उनके स्पोर्ट्स से जुड़े सपनों को पूरा करने के मौके देने पर कितना ज़ोर देता है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज के शेड्यूल में होगा बदलाव?

नई दिल्ली,13 अगस्त 2026। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच 13, 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीन मैचों की टी 20 आई सीरीज की पुष्टि की थी। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक एसीबीअब इस शेड्यूल में थोड़ा बदलाव करना चाहता है। अफगानिस्तान बोर्ड की मंशा है कि एक मुकाबला 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आयोजित किया जाए। इस दिन आंशिक छुट्टी होने के कारण स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, इसी को ध्यान में रखते हुए एसीबी ने 13 या 15 सितंबर वाले मैच को 14 सितंबर को कराने का प्रस्ताव रखा है।

ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया अधिकारों पर बातचीत जारी

रिपोर्ट्स के अनुसार एसीबी इस घरेलू टी 20 आई सीरीज के टीवी प्रसारण अधिकारों के लिए सोनी स्पोर्ट्स और स्टार स्पोर्ट्स जैसे प्रमुख ब्रॉडकास्टर्स के साथ बातचीत कर रहा है। डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार फैनकोड के पास रहने की संभावना है, जबकि एसीबी यूनिवर्स मीडिया राइट्स और ग्राउंड ब्रांडिंग का काम संभालेगा। आईसीसी के फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम के तहत यह अफगानिस्तान की होम सीरीज है, लेकिन सुरक्षा और सुविधाओं के मद्देनजर इसे भारत में आयोजित किया जा रहा है। यह पहला मौका होगा जब अफगानिस्तान की टीम भारत में ही भारत के खिलाफ अपनी मेजबानी में खेलेगी। यह सीरीज आगामी एशियाई खेलों की तैयारियों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होगी।

भारत का बांग्लादेश दौरा रद्द होना लगभग तय

भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर में टी 20 आई सीरीज पक्की होने के बाद अब भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरा रद्द होना लगभग तय माना जा रहा है। इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 1 से 13 सितंबर के बीच भारत के खिलाफ 3 वनडे और 3 टी 20 आई मैचों का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों और सरकारी हरी झंडी न मिलने के कारण यह दौरा अधर में लटक गया था। हालांकि बांग्लादेश के खेल मंत्री अमीनुल हक ने विवाद सुलझने की उम्मीद जताई थी, लेकिन नए घटनाक्रम के बाद भारतीय टीम का बांग्लादेश जाना अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा है।

टीम इंडिया में शामिल हुए आकिब नबी

नई दिल्ली,13 अगस्त 2026। श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को शामिल किया गया है। शुरुआत में नजरअंदाज किए जाने के बाद,जसप्रीत बुमराह के चोटिल होकर बाहर होने पर आकिब को भारतीय टीम में बुलावा मिला। आकिब नबी भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा बनने वाले जम्मू-कश्मीर के इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए हैं।

घरेलू क्रिकेट में बरपाया कहर

आकिब नबी पिछले कुछ समय से घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दो सालों में उन्होंने लाल गेंद से शानदार गेंदबाजी करते हुए घरेलू क्रिकेट में कुल 104 विकेट चटकाए हैं। हालिया रणजी ट्रॉफी सीजन में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लिए 60 विकेट झटके थे और अपनी टीम को पहली बार रणजी चैंपियन बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इतने बेहतरीन आंकड़ों के बावजूद उन्हें टीम इंडिया में एंट्री के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा।

सलेक्शन पर आकिब नबी का बड़ा बयान

टीम इंडिया में चुने जाने के बाद बीसीसीआई द्वारा जारी एक वीडियो में आकिब ने कहा,आज हो या कल, मुझे पूरा यकीन था कि मैं भारतीय टीम में जरूर शामिल होऊंगा क्योंकि जब आप इतने सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं,तो आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है। गेंदबाजी करते समय भी मेरी यही सोच रहती है कि मेरा काम सिर्फ विकेट लेना है, बाकी सब भगवान के हाथ में है। जब मुझे बुलावा आया तो बेहद खुशी हुई, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है।

अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार आकिब

आकिब नबी ने अपनी मानसिकता का जिक्र करते हुए आगे कहा कि एक क्रिकेटर के तौर पर आपको हमेशा यही सोच रखनी होती है कि आपका काम मैदान पर बेस्ट देना है। जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो चयनकर्ता और बाकी लोग खुद आपको देखते हैं। आकिब को पूरा भरोसा था कि उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी और आखिरकार उन्हें देश के लिए खेलने का सुनहरा मौका मिल ही गया।

नाम परिवर्तन सूचना

मै बिलसन खलखो पिता मूसा खलखो आयु 30 वर्ष, निवासी ग्राम-चिरींगा थाना कल्याणपुर, नवानगर तहसील दरिमा जिला सरगुजा छ0ग0 ।

यह कि मेरे पुत्र एरिक खलखो का जन्म दिनांक-10/12/2025 को जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 मे हुआ है। तथा जन्म प्रमाण पत्र मे एफिक खलखो दर्ज हो गया है जो गलत है । मेरा पुत्र का सही नाम एरिक खलखो ARIC XALXO है जो सत्य व सही है। उक्त जन्म प्रमाण पत्र सही नाम एरिक खलखो ARIC XALXO दर्ज किये जाना उचित एवं आवश्यक है। जिस हेतु मै अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

शपथग्रहिता
बिलसन खलखो

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ- 20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक अशोक कुमार अग्रवाल आ0 श्री मोहरीलाल अग्रवाल, निवासी अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व की मोहल्ला - सदर रोड़, नगर अम्बिकापुर शीट नम्बर-11क स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 3196/4817/55, 3196/4817/62 रकबा 418 वर्गफीट, 210 वर्गफीट भूमि को अपने भाई अनावेदक- अनिल कुमार अग्रवाल आ0 श्री मोहरीलाल अग्रवाल, निवासी अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर के पक्ष में दान करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा की प्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-20.08.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक-04/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ- 20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका श्रीमती माया सिंह आ0 / पति स्व0 सोमेन्द्र प्रताप सिंह जाति अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया निवासी बाबूपारा, हैं कि मोहल्ला - बाबूपारा, शीट नम्बर 9 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3467/4866/60 रकबा 118.2 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक - 21.08.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 06.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

मेडिकल कॉलेज निर्माण पर स्वास्थ्य मंत्री की नजर,गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर

निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री,गुणवत्ता से समझौता नहीं करने का निर्देश...

■ मेडिकल कॉलेज निर्माण की रफ्तार परखी,स्वास्थ्य मंत्री बोले...गुणवत्ता के साथ समयबद्धता जरूरी

■ अधूरे मेडिकल कॉलेज का मंत्री ने लिया जायजा अधिकारियों से कहा...काम में न हो लापरवाही...

कोरबा,13 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिले में निर्माणाधीन शासकीय मेडिकल कॉलेज के कार्यों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया, इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति,गुणवत्ता तथा निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप हो रहे काम का जायजा लिया, निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से निर्माण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शासकीय मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण संस्थान साबित होगा। मेडिकल कॉलेज के निर्माण से न केवल कोरबा जिले बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी,उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ-साथ समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता बताई,ताकि निर्धारित समय में आमजन को इसका लाभ मिल सके।

निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता का लिया जायजा-निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई, स्वास्थ्य मंत्री ने निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों से वर्तमान स्थिति,कार्ययोजना तथा निर्माण की गति के संबंध में जानकारी प्राप्त की, उन्होंने निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री और कार्य की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज जैसी महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण केवल भवन तैयार करने तक सीमित नहीं है,बल्कि इसके माध्यम से भविष्य में क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत आधार मिलना है,इसलिए निर्माण के प्रत्येक चरण में निर्धारित तकनीकी मानकों और गुणवत्ता का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समय-सीमा के अनुरूप काम पूरा करने के निर्देश

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए,उन्होंने कहा कि निर्माण में अनावश्यक विलंब होने से परियोजना की लागत और आम लोगों को मिलने वाली सुविधाओं पर असर पड़ सकता है,इसलिए कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए सामने आने वाली तकनीकी अथवा प्रशासनिक समस्याओं का समय पर निराकरण किया जाए,निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के साथ निर्माण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कार्य की लगातार मॉनिटरिंग करने तथा निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में बनेगा महत्वपूर्ण संस्थान

मेडिकल कॉलेज के निर्माण को जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बेहतर चिकित्सा अधोसंरचना विकसित करना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है,मेडिकल कॉलेज के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के लिए दूसरे बड़े शहरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकेगी,उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अधोसंरचना का विकास आवश्यक है, मेडिकल कॉलेज के साथ इससे जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को भी प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

नियमित समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग पर जोर

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में चल रही योजनाओं की नियमित समीक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया,मंत्री ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और इसके लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा करना जरूरी है,उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी भी समस्या का समय पर समाधान किया जाए और कार्य की प्रगति की नियमित निगरानी हो, इससे परियोजना को समय-सीमा में पूरा करने के साथ उसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा सकेगी, कोरबा में शासकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा होने के बाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है, ऐसे में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, गति और समय-सीमा पर स्वास्थ्य विभाग की लगातार नजर महत्वपूर्ण होगी, फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण के बाद अधिकारियों को दिए गए दिशा-निर्देशों से परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर स्पष्ट दिखाई दिया है।

कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारी रहे मौजूद

निरीक्षण के अवसर पर कोरबा जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे,स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी लेते हुए परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए निर्माण कार्य की नियमित समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है, ताकि मेडिकल कॉलेज का लाभ निर्धारित समय में आमजन को मिल सके।

रायपुर-नागपुर रूट पर ट्रेन से 1.96 करोड़ का विदेशी सोना जब्त,दो संदिग्ध गिरफ्तार

रायपुर,13 अगस्त 2026। रायपुर-नागपुर रेल मार्ग पर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। आरपीएफ क्राइम ब्रांच रायपुर-नागपुर और डीआरआई नागपुर की संयुक्त टीम ने हावड़ा-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस से करीब 1.96 करोड़ रुपये का विदेशी सोना बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान दो संदिग्धों को भी पकड़ा गया है। टीम ने आरोपियों के कब्जे से कुल 1.242 किलोग्राम सोना बरामद किया, जिसमें सात सोने के बिस्किट और एक सोने की छड़ शामिल है। जब्त सोने की अनुमानित कीमत 1,96,34,307 बताई गई है। जानकारी के मुताबिक आरपीएफ क्राइम ब्रांच नागपुर के निरीक्षक को सूचना मिली थी कि हावड़ा-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में दो लोग विदेशी सोना लेकर सफर कर रहे हैं। सूचना के आधार पर आरपीएफ रायपुर और नागपुर की

टीम ने डीआरआई नागपुर के अधिकारियों के साथ मिलकर ट्रेन की जांच शुरू की। संयुक्त टीम ने ट्रेन नंबर 12262 में रायपुर से नागपुर के बीच तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान टीम को ट्रेन के बी-12 कोच में दो संदिग्ध व्यक्ति मिले। दोनों को भंडारा-नागपुर के बीच हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर उनके पास से विदेशी सोना बरामद हुआ। सोने का वजन करने पर कुल मात्रा करीब 1.242 किलोग्राम निकली। इसमें सात गोल्ड बिस्किट और एक गोल्ड बार शामिल था। कार्रवाई के बाद आरपीएफ ने दोनों संदिग्धों और बरामद सोने को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए डीआरआई नागपुर के सुपुर्द कर दिया। डीआरआई ने मामले में कस्टम अधिनियम,1962 की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। अब जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि विदेशी सोना कहां से लाया गया था और इसे किसे पहुंचाया जाना था। दोनों संदिग्धों से पूछताछ के साथ-साथ सोने की तस्करी से जुड़े संभावित नेटवर्क और अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

27 मौतें,13 साल का इंतजार...अब 31 अगस्त को झीरम कांड में आएगा सबसे बड़ा फैसला

रायपुर,13 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम कांड मामले में एनआईए की विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। तीन दिनों तक चली अंतिम बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत 31 अगस्त को मामले में फैसला सुनाएगी। अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क अदालत के सामने रखे।

मामले की अंतिम सुनवाई सोमवार से शुरू हुई। पहले दिन एनआईए की ओर से अंतिम तर्क पेश किए गए। इसके बाद मंगलवार को बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें अदालत के सामने रखीं। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुनाने की तारीख 31 अगस्त तय कर दी। अब मामले से जुड़े पक्ष अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

10 आरोपियों के खिलाफ चल रही थी सुनवाई : झीरम कांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने की थी। एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार हमले में 27 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 35 लोग घायल हुए थे। मामले में चार लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा माओवादी गतिविधियों से जुड़े कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया। जांच के दौरान एनआईए ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है और बाकी आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई जारी थी।

25 मई 2013 को हुआ था झीरम हमला

झीरम कांड 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की झीरम घाटी में हुआ था। उस समय कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था। इसी दौरान घात लगाए माओवादियों ने काफिले पर हमला कर दिया था। हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ सुरक्षाकर्मी और आम लोग भी मारे गए थे। तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल और बस्तर टाइगर के नाम से पहचाने जाने वाले महेंद्र कर्मा की भी इस हमले में मौत हुई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल समस्या को लेकर कई गंभीर सवाल उठे थे।

कांग्रेस ने लगाए थे गंभीर आरोप

हमले के बाद कांग्रेस ने तत्कालीन भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए जांच की मांग की थी। वहीं जांच एजेंसियों ने मामले में नक्सली हमले के एंगल से जांच आगे बढ़ाई। कई वर्षों तक चली जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद अब मामला अंतिम चरण में पहुंच गया है। अदालत के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई तय होती है।

छत्तीसगढ़ पुलिस के 12 अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति पदक

रायपुर,13 अगस्त 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 12 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की थी। अब इन पदकों को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. विष्णुदेव साय प्रदान करेंगे। विशिष्ट सेवाओं के लिए रामावतार सिंह राजपूत, सहायक उप निरीक्षक, रक्षित केंद्र जिला धमतरी को राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा। वहीं, सराहनीय सेवाओं के लिए 11 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा।

इन अधिकारियों को मिलेगा सराहनीय सेवा पदक

- रामगोपाल गर्ग - पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज
- शशिमोहन सिंह - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़
- श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा - पुलिस अधीक्षक, रायपुर ग्रामीण
- राजश्री मिश्रा - पुलिस अधीक्षक, एटीएस, पुलिस मुख्यालय रायपुर
- निवेदिता पाल - सेनानी, 6वीं वाहिनी छसबल, रायगढ़
- मनीषा ठाकुर रावटे - सेनानी, 20वीं वाहिनी छसबल, महासमुंद
- तारकेश्वर पटेल - अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जिला पुलिस, मध्य पुलिस आयुक्त, रायपुर नगरीय
- उनैजा खातून अंसारी - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय रायपुर
- जयलाल मरकाम - सहायक सेनानी, प्रथम वाहिनी छसबल, भिलाई
- हजारी लाल साहू - प्लाटून कमांडर, 20वीं वाहिनी छसबल, महासमुंद

42 पदों के लिए परीक्षा,किसी के 80 तो किसी के 100% अंक जीएसटी भर्ती पर ननकीराम कंवर ने पीएम मोदी को लिखा खत

रायपुर,13 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कंवर ने जीएसटी विभाग की वर्ष 2021 और 2022 में हुई पदोन्नति परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है। कंवर ने आरोप लगाया कि राज्य कर निरीक्षक के 42 पदों के लिए हुई परीक्षा में करीब 350 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और परीक्षा प्रक्रिया में कई गंभीर अनियमितताएं हुईं।

42 पदों के लिए करीब 350 कर्मचारियों ने दी परीक्षा

ननकीराम कंवर के मुताबिक, राज्य कर निरीक्षक के 42 पदों के लिए दो वर्षों में परीक्षा आयोजित की गई थी। उनका आरोप है कि विभागीय अधिकारियों ने व्यापमं से सहयोग लेने के बजाय खुद परीक्षा आयोजित की। कंवर ने इसी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में रखते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है।

80 से 100 फीसदी तक अंक मिलने पर उठाए सवाल

कंवर ने आरोप लगाया कि परीक्षा में चयनित कुछ कर्मचारियों के अंक 80 से 100 प्रतिशत तक रहे। उनके मुताबिक, इतने अधिक अंक इस

बात का संकेत देते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया हो सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चयनित लोगों में तत्कालीन विभागीय आयुक्त समीर बिश्नोई के पीए और अन्य अधिकारियों से जुड़े लोग शामिल थे।

उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा पर भी सवाल

ननकीराम कंवर ने परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि उत्तर पुस्तिकाओं पर न तो कोई मोहर लगी थी और न ही अधिकारियों के हस्ताक्षर थे। कंवर के अनुसार, ऐसी स्थिति में उत्तर पुस्तिकाओं में बाद में बदलाव किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कंवर ने अपने पत्र में तत्कालीन आयुक्त समीर बिश्नोई का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि बिश्नोई वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में जेल में हैं। इसी आधार पर कंवर ने परीक्षा प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है।

पीएम मोदी से ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग

ननकीराम कंवर ने प्रधानमंत्री से पूरे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में गड़बड़ी साबित होती है तो संबंधित भर्ती को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। फिलहाल कंवर की ओर से लगाए गए आरोपों पर संबंधित विभाग या परीक्षा में चयनित कर्मचारियों का पक्ष सामने नहीं आया है। मामले में केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग पर आगे क्या कार्रवाई होती है,यह देखना अहम होगा।

सर्पदंश मुआवजा घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को,डीजीपी ने दिए बड़े संकेत

बिलासपुर,13 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने बिलासपुर में कहा कि सर्पदंश मुआवजा घोटाले की जांच विशेषज्ञ एजेंसी को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और आर्थिक अनियमितताओं की जांच के लिए विशेषज्ञ एजेंसी को जांच सौंपने का प्रस्ताव भेजा गया है। उनके इस बयान के बाद अब इस बहुचर्चित घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपे जाने की संभावना है। डीजीपी ने पुलिस की जांच और अब तक की कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच ईमानदारी और साफ तरीके से की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इसकी जांच किसी विशेषज्ञ एजेंसी से कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे आर्थिक गड़बड़ी से जुड़े पहलुओं की जांच और बेहतर तरीके से हो सकेगी। जशपुर में पिछले तीन साल में सर्पदंश से 96 मौतें दर्ज हुई हैं। वहीं, अकेले बिलासपुर में 431 मौतें दिखाकर 17 करोड़ 24 लाख रुपए का मुआवजा बांट दिया गया। बेलतरा विधायक सुशांत

शुक्ला ने यह मामला विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। इसके बाद राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। सरकारी नियमों के अनुसार सर्पदंश से मौत होने पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। जांच में सामने आया कि इसी योजना का गलत फायदा उठाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। कई सामान्य मौतों को भी सर्पदंश से हुई मौत बताकर मुआवजा ले लिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ मामलों में परिजनों की जानकारी या सहमति के बिना ही मुआवजे की राशि निकाल ली गई।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)